माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024–25 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

1. पिछले साल प्रदेश में अभूतपूर्व बरसात के कारण अनेक प्रदेशवासी असमय ही काल का ग्रास बन गए। मैं, सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति प्रदेश सरकार तथा इस माननीय सदन की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इस वर्षा के कारण प्रदेश में जान और माल दोनों का ही व्यापक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में समय लगेगा।

2. यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। गत् वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि जनसेवा के लिए **'अच्छे शासन (good Government)'** के साथ **'अच्छे प्रशासन (good governance)'** की ज़रूरत है, और यह भी कहा था कि हमें हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। हमने इस बदलाव की शुरूआत कर दी है। मेरी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। अब तक, 1 लाख 15 हज़ार कर्मचारियों ने OPS को चुना। OPS में आए सभी कर्मचारी General Provident Fund (GPF) subscription प्राप्त कर चुके हैं। NPS से OPS में आए लगभग 5 हज़ार कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद OPS के अनुसार Pay and Pension Orders (PPOs) जारी किये गए हैं। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की 'स्टार्ट–अप योजना' शुरू कर दी गई है। इस योजना के दो भागों क्रमशः 'राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना' के अन्तर्गत 50 प्रतिशत् उपदान पर ई–टैक्सी और 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के

अन्तर्गत निजि भूमि पर 50 प्रतिशत् उपदान पर 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान है तथा इनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। तीसरे और अंतिम चरण की योजना का वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है। प्रदेश की लगभग 2 लाख 37 हज़ार महिलाओं की मासिक पेंशन 1,150 रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये कर दी गई है। लाहौल–स्पिति की सभी महिलाओं को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह इसी वित्तीय वर्ष से मिलने आरम्भ हो गए हैं। हम चरणबद्ध तरीके से, प्रदेशवासियों के साथ चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा करेंगे लेकिन हमें समझना होगा कि इसके लिए पुराने समय के नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से काम नहीं चल सकता। सरकार को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संगठन, संरचना, तकनीक और अपने आचार व्यवहार को बदलना होगा। प्रदेश सरकार ने गत् एक वर्ष में इस दृष्टि से बहुआयामी और बुनियादी परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की है। इन परिवर्तनों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। **'व्यवस्था परिवर्तन'** की यह प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज़ किया जाएगा।

3. 21वीं सदी में अच्छी सरकार और सुशासन की अवधारणा पुराने विचारों और प्राचीन संस्थाओं से तय नहीं हो सकती। 21वीं सदी के दूसरे दशक के 5वें वर्ष में प्रवेश करते समय हमें पूरी दुनिया की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है।

4. अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि आज Global World में दुनिया के सभी संघर्षों, युद्ध और ज्वलंत मुद्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। गाज़ा पट्टी में इज़राईल–फिलिस्तीन संघर्ष हो या युक्रेन

युद्ध, इनका असर किसी न किसी तरह हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

5. वैसे तो परिस्थितियों और अवसरों में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है किन्तु हर बदलाव की एक विशेषता होती है। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर विश्व का बढ़ता औसत तापमान और उसके दुष्प्रभाव जैसी चुनौतियां हैं, वहीं Disruptive Technologies के नैतिक प्रयोग से बेहतरी लाने की अपार सम्भावनाएं हैं। हमारी सरकार Artificial Intelligence के प्रयोग से उपलब्ध अवसरों पर गम्भीरता से काम करेगी। इसके माध्यम से समग्र विकास और जन कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा जोकि प्रदेश की **'आत्मनिर्भरता'** की ओर हमारी यात्रा को गति देगा।

6. अध्यक्ष महोदय, विकास का रास्ता कठिन है, इसमें बाधाएं भी हैं, परन्तु हम किसी भी बाधा को विकास के रास्ते में रूकावट नहीं बनने देंगे। कठिन समय में कठिन निर्णय लेने की क्षमता का नाम ही सुशासन है। मेरी सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। गत् वर्ष की प्राकृतिक आपदा के दौरान हमने यह क्षमता प्रदर्शित भी की है। नीति आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं द्वारा की गई प्रशंसा के साथ–साथ विश्व बैंक द्वारा भी हमारी सरकार द्वारा किये गए राहत कार्यों की सराहना की गई है।

7. सरकार ने आपदा प्रभावितों को तुरन्त राहत पहुँचाने के लिए वर्षों से चले आ रहे राहत एवम् पुनर्वास नियमों में बदलाव किया और 4 हज़ार 500 करोड़ रुपये की विशेष राहत पैकेज जारी की। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार को अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के बाद भी केन्द्र से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु फिर भी हमने प्रदेश स्तर पर अपनी प्राथमिकताएं तय कीं और हर प्रभावित व्यक्ति को यथा–सम्भव सहायता प्रदान की। हमने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली

राशि को 1 लाख 30 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये किया जोकि अभूतपूर्व बढ़ौतरी है। इसी प्रकार कच्चे घर के आंशिक नुकसान के मुआवज़े को 6 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है। दुकानों और ढाबों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को चार गुणा बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपये किया और गौशालाओं के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि को सिर्फ 3 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया। इतना ही नहीं हमने आपदा प्रभावित परिवारों को घर किराये पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हज़ार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र में 10 हजा़र रुपये प्रतिमाह की राशि मंजूर की। इस बढ़ी हुई सहायता राशि की मदद से 2 हज़ार 968 लाभार्थियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए, 10 हज़ार से अधिक लाभार्थियों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत के लिए, 3 हज़ार 648 लाभार्थियों को गौशालाओं के लिए तथा लगभग 1 हज़ार 800 लाभार्थियों को पशुधन के नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 2 हज़ार 600 किसानों को उनकी फसल और जमीन को हुए नुकसान के लिए तथा 507 दुकानों व ढाबों की मुरम्मत के लिए सहायता प्रदान की गई। अन्य सभी लाभार्थियों को मिलाकर हमारी सरकार द्वारा 22 हज़ार 130 लाभार्थियों को तुरन्त राहत सहायता पहुँचायी गई। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 31 मार्च, 2024 तक LPG Connection तथा खाने–पीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है तथा सम्भवतः किसी भी आपदा की स्थिति में पूरे देश में सबसे अधिक liberal financial package रही है।

8. हमारी सरकार केवल और केवल जन कल्याण के लिए सत्ता में आई है। मैंने बार–बार कहा है कि

हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। हम प्रदेश के हर नागरिक के दूरगाामी हित को ध्यान में रख कर कार्य कर रहे हैं। समाज के उपेक्षित, वंचित और हाशिये पर रहने वाले लोग हमारे लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।

9. 'मुख्य मन्त्री सुख आश्रय योजना' समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की मेरी सरकार की नीयत और नीति का एक उदाहरण है जिसके तहत 4 हज़ार से अधिक बच्चों को 'Children of the State' के रूप में अपनाया गया है। इस योजना के माध्यम से हम हर प्रदेशवासी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार हर समय प्रत्येक प्रदेशवासी के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है।

10. अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम है लोगों के रोज़मर्रा जीवन में सरकार के साथ सम्बन्धों में सुधार हो, नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाए और सरकारी सेवाओं को घर द्वार पर उपलब्ध करवाये। आम आदमी को ज़मीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए हमने राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन प्रारम्भ किया है। इन विशेष अदालतों में अभी तक 89 हज़ार 91 इन्तकालों तथा तकसीम से सम्बन्धित लगभग 6 हज़ार मामलों का निपटारा किया गया जो वर्षों से लम्बित थे। हमारी सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से Forest Clearances से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप लगभग 10 वर्षों से अधिक लम्बित जल विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्तावों में पिछले 1 वर्ष के दौरान Forest Clearances पर सैद्धान्तिक मंजूरी और 71 प्रस्तावों पर भारत सरकार की अंतिम मंजूरी प्राप्त की गई। सरकार द्वारा NGT के 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' पर

किये गए फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सशक्त चुनौती दी गई। हमारे प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NGT के फैसले को पलट कर 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' पर मोहर लगाई गई जिससे शिमला निवासियों को राहत मिली है। इसी ऐतिहासिक फैसले के कारण जाठिया देवी में एक आधुनिकतम township बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।

11. मेरी सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश का अग्रणीय राज्य है। हमने, प्रदेश में 6 'ग्रीन कॉरिडोर' स्थापित किये हैं। हिमाचल ने Green Hydrogen और Ammonia Project के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे 4 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 3 हज़ार 500 से अधिक प्रदेशवासियों को रोज़गार मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हिमाचली युवाओं को e-vaahan पर 50 प्रतिशत् subsidy देने का निर्णय लिया है। इस योजना को लेकर युवाओं में बहुत उत्साह है। इसी प्रकार, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, Roof Top Solar Plants तथा गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

12. कुछ वर्ष पहले तक हिमाचल प्रदेश 'देश के बिजली राज्य' के रूप में जाना जाता था। परन्तु, पूर्व में अपनाई गईं गलत नीतियों के कारण एक तरफ नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के उत्साह में कमी आई है और दूसरी तरफ पूर्व सरकारों द्वारा जिन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गए हैं उनकी कुछ बातें प्रदेश के हित में नहीं हैं। इन नीतियों में और भी सुधार और बदलाव की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा देश और दुनिया का भविष्य है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। इस दिशा में निवेश और रोज़गार की

भी अपार सम्भावनाएं हैं। मेरी सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

13. अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है। किसी भी समाज को प्रगति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करना समय की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि जब–जब बड़े बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तब–तब परम्परागत तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। इनसे थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। परन्तु यह व्यवधान अस्थाई होता है और इसके बाद ही नव–निर्माण सम्भव होता है। आज का समय हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व से यही मांग कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे और इस बदलाव की सहायता से समृद्ध एवम् सम्पन्न हिमाचल की गाथा लिखकर '**आत्मनिर्भरता**' की ओर बढ़ेंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और '**आत्मनिर्भर हिमाचल**' की जो परिकल्पना की हैं, उसके मुख्य बिन्दु हैंः

- **'आत्मनिर्भर हिमाचल'**
- समृद्ध किसान हिमाचल
- हरित और स्वच्छ हिमाचल
- बिजली राज्य हिमाचल
- पर्यटन राज्य हिमाचल
- कुशल और दक्ष हिमाचल
- स्वस्थ एवम् शिक्षित हिमाचल
- निवेशक मित्र हिमाचल
- नशा मुक्त हिमाचल
- अवैध खनन मुक्त हिमाचल
- समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

15. यह सम्पन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समर्थ, सबल और **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की परिकल्पना है। इस बदलाव का नेतृत्व प्रदेश के ऊर्जावान युवा और सशक्त महिलाएं करेंगी। यह ऐसे हिमाचल की तस्वीर है जिसमें एक छोर पर गाँव के स्तर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवम् सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास की पहल से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि होगी वहीं दूसरे छोर पर हिमाचल के शिक्षित, कुशल और आधुनिक तकनीक में दक्ष युवक और युवतियां प्रदेश, देश और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमें स्थानीय ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा दुग्ध उत्पादन पर आधारित **'आत्मनिर्भर'** अर्थव्यवस्था के निर्माण से लेकर आधुनिकतम तकनीक के उपयोग तक end to end, eco-system का निर्माण करना है। इस बजट के माध्यम से मैं **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की कल्पना को साकार करने का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सभी आवश्यक बदलाव तथा structural सुधार 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम कुछ ही समय बाद आने शुरू हो जाएंगे जिसके साथ ही **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की परिकल्पना को 2032 तक पूरी करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

16. हमारी सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछली सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबन्धन और फिजूलखर्ची के कारण हमारी सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में गलत नीतियों के चलते आज ऋण के रूप में 87 हज़ार 788 करोड़ रुपये की कुल देनदारियां उत्पन्न हो गई हैं। 2018 में कुल देनदारियां 47 हज़ार 906 करोड़ रुपये थी जोकि 2023 में बढ़कर 76 हज़ार 651 करोड़ रुपये हो चुकी थीं। पूर्व सरकार ने हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें अपने कार्यकाल के अंत में लागू की जोकि

पहले भी लागू की जा सकती थीं। इस विलम्ब के कारण कर्मचारियों के वेतन के arrears बढ़ते चले गए और उनकी देनदारी हमारी सरकार के सुपुर्द कर दी गई। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया। हमने सत्ता सम्भालते ही कड़े फैसले लेते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिये। State Excise Policy में बदलाव के कारण 2023–24 में State Excise Duty में पिछले वर्ष की तुलना में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि अपेक्षित है। पिछले वर्ष 1 हज़ार 370 करोड़ रुपये VAT के रूप में प्राप्त हुए थे जोकि 2023–24 के अंत तक 1 हज़ार 773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार State Excise Duty तथा VAT में लगभग 22 प्रतिशत् की वृद्धि अनुमानित है। Milk Cess के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार से जुटाए गए संसाधनों को प्रदेशवासियों के विकास तथा कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी चाहे इसके लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने पड़ें।

17. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को **'आत्मनिर्भर'** बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। हमारी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को **'Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)'** के आधार पर हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 हज़ार 906 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के NPS से OPS में आए कर्मचारियों की contribution के लगभग 8 हज़ार करोड़ रुपये भारत सरकार के पास पड़े हैं। 'Bhakra-Beas Management Board' की विभिन्न परियोजनाओं में हिस्से के रूप में प्रदेश सरकार को लगभग 4 हज़ार 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने शेष हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश सरकार को 22 हज़ार 406 करोड़

रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं। मैं, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को **'आत्मनिर्भरता'** की ओर ले जाने के लिए हम सब मिलकर इस राशि को शीघ्र पाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न करें।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

18. अध्यक्ष महोदय, 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3 प्रतिशत् की दर से बढ़ने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत् या उससे अधिक की वृद्धि दर अनुमानित है। किन्तु कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि दर केवल 1.8 प्रतिशत् अनुमानित है, जोकि कृषि क्षेत्र में गम्भीर समस्याओं की ओर इशारा करती है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

19. अध्यक्ष महोदय, 2023-24 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2022-23 के दौरान दर्ज 6.9 प्रतिशत् की तुलना में 7.1 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हज़ार 199 रुपये रहने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

विकास बजट

20. 2024-25 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9 हज़ार 990 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। 'अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम' के लिए 2 हज़ार 516 करोड़ रुपये, 'जनजातीय विकास कार्यक्रम' के लिए 899 करोड़ रुपये तथा 'पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के लिए 110 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं के लिए 5 हज़ार 280 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित किये गए हैं।

21. प्रदेश के विकास में आ रही चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए योजना विभाग में एक **"Himachal Pradesh Transformation Cell (HPTC)"** की

स्थापना की जाएगी। यह Cell स्थानीय, राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर best practices के आधार पर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सुझाव देगा। इसके साथ ही विकास प्रक्रिया की monitoring तथा evaluation के लिए योजना विभाग में **"Sustainable Development Goals Coordination Centre"** की स्थापना की जाएगी। ये दोनों इकाईयाँ आगामी वित्तीय वर्ष से कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

कृषि/Value addition/पशुपालन एवं गौ–संरक्षण

22. अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जोकि प्रदेश की लगभग 69 प्रतिशत् जनसंख्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। प्रदेश के कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है।

23. मैं, प्राकृतिक खेती में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के तीसरे चरण में एक नई योजना **''राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट–अप योजना''** की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में, प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को **'ज़हर मुक्त खेती'** के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूँ में यूरिया और 12–32–16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल न करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा करता हूँ। बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूँ को 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के MSP पर खरीदा जाएगा। हमारी सरकार द्वारा दिये जाने वाला यह MSP पूरे देश

में सबसे अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37 हज़ार मिट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में हमारी सरकार का यह एक और प्रयास है। इससे प्राकृतिक खेती करने वालों को एक सुरक्षा चक्र मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होंगे। इससे 15 हज़ार एकड़ की भूमि को Web Portal के माध्यम से प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में certify किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 10 नए 'Farmer Producer Organizations (FPOs)' गठित किये जाएंगे। 2024–25 में, इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इसके साथ ही, फैंसिंग के लिए जालीदार बाड़ तथा कांटेदार तार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में व्यय किये जाएंगे।

24. मैं, 'हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन' के अन्तर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2 हज़ार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को समान रूप से विकसित करने की घोषणा करता हूँ। इस मिशन के अन्तर्गत climate के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में high value फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कृषकों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।

25. वर्ष 2023 को पूरे विश्व में 'International Year of Millets' के रूप में मनाया गया। प्रदेश में मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा अन्य प्रदेशवासियों को मोटे अनाज की सांस्कृतिक महत्ता तथा nutritional value के बारे में सजग किया जाएगा।

26. 2024–25 में 'JICA Phase-II Project' के अन्तर्गत 50 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त

लाभार्थी कृषकों के उत्पादन में processing के माध्यम से value addition का प्रावधान किया जाएगा तथा इन उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक marketing infrastructure का विकास किया जाएगा।

27. अध्यक्ष महोदय, मैं 2024–25 में निम्नलिखित मंडियों के निर्माण तथा उन्नयन की घोषणा करता हूँः–

- ✓ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार; कुल्लू में चौरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू; मण्डी में टकोली और कांगनी; काँगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर; तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा।

28. मंडियों में होने वाली गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए इनकी सभी प्रक्रियाओं की digitization के साथ–साथ कृषि उपज मंडी समितियों के यार्डों तथा 'राज्य कृषि विपणन बोर्ड' की कार्यप्रणाली को digitize किया जाएगा।

29. किसानों की सुविधा के लिए Chat Bot और AI पर आधारित भू–अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के database सहित एक web आधारित कृषि पोर्टल और Mobile App बनाया जाएगा। इसमें 'सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग' तथा 'Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC)' से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

30. सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाएंगे। इसके लिए एक **'Centre of Excellence for Vegetable Nursery Production'** खोला जाएगा जोकि 8 से 10 लाख पौधे एक साल में उपलब्ध करवा सकेगा।

31. High Yield बीजों की multiplication के लिए पूरे प्रदेश के सरकारी farms को चरणबद्ध ढंग से पुनर्गठित किया जाएगा। 2024 में काँगड़ा में भट्टू फार्म, सोलन में बेरटी फार्म तथा सिरमौर भंगाणी फार्म को अपग्रेड किया जाएगा तथा इनके माध्यम से उच्च कृषि तकनीक, नर्सरी उत्पादन इत्यादि को showcase किया जाएगा।

32. मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं, 1 अप्रैल, 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्रमशः वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर; और, 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी करने की घोषणा करता हूँ। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाज़ार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाज़ार में बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा। बढ़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा। प्राकृतिक तकनीक से उगाई गई गेहूँ को सरकार द्वारा certify किया जाएगा तथा उत्पाद को सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हम चरणबद्ध

तरीके से किसान परिवार को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा कर सकें। 2024–25 में, इस पर लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी।

33. Himachal Pradesh Milk Federation (MILKFED), कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दूध उत्पादन सोसाइटियों से Agricultural Produce Market Committee (APMC) द्वारा ली गई market fees reimburse करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सोसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमेटी के पास काफी समय तक पड़ा रहता है। मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी। इससे इन सोसाइटियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुँचेगा।

34. मेरा लक्ष्य है कि किसानों और पशु–पालकों को न केवल दूध उत्पाद को Cost Based Price मिले बल्कि Quality Bonus भी मिले। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समयावधि को ध्यान में रख कर कार्य कर रही है। यह सरकार एवम् पशु–पालकों के संयुक्त प्रयास से सम्भव हो पाएगा। प्रदेश के युवाओं में पशुपालन से सम्बन्धित कौशल के विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से नये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे।

35. 'हिम–गंगा' योजना के अन्तर्गत मैं वर्ष 2024–25 के दौरान काँगड़ा के ढगवार में 1.5 LLPD (Lakh Litre Per Day) की क्षमता वाले **'Fully Automated**

Milk and Milk Products Plant' की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 LLPD कर दिया जाएगा। इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा जिससे कि मांग से अधिक दूध को लम्बे समय तक preserve करके रखा जा सके। इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आईसक्रीम, flavoured milk, processed cheese और अन्य उत्पाद तैयार किये जाएंगे। इसके साथ ही, यहाँ UHT (Ultra Heat Technology) से पैकिंग की सुविधा भी उपलव्ध होगी।

36. दत्तनगर 'Milk Processing Plant' में 50 हज़ार LPD की क्षमता का एक अतिरिक्त सयंत्र चालू कर दिया जाएगा तथा वर्तमान में विभिन्न जिलों में काम कर रहे दूध सयंत्रों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

37. ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'Milk Processing Plants' स्थापित किये जाएंगे जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

38. स्थानीय युवाओं को किसानों/collection centres से milk processing plants तक दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत् उपदान पर 200 refrigerated milk vans उपलब्ध करवाई जाएंगी।

39. पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं सोलन जिले के दाड़लाघाट में **'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र'** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ जिसकी सहायता से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

40. विशेषज्ञ पशुचिकित्सकों द्वारा गम्भीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44

mobile veterinary vans क्रय कर ली गई हैं। यह सेवा वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आरम्भ कर दी जाएगी। प्रत्येक वैन में एक Veterinary Doctor तथा एक pharmacist तैनात होगा। पशु–पालक प्रदेश में कहीं से भी टॉल फ्री फोन नम्बर 1962 पर कॉल करके पशुओं के उपचार की सुविधा या पशुपालन से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

41. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत ऊना जिले के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से 44 करोड़ रुपये की लागत से एक **'उत्कृष्टता केन्द्र'** स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर हस्तांतरित हो चुकी है।

42. बदलते समय में पशुपालन विभाग के संगठनात्मक ढाँचे के पुनर्गठन एवम् पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है। अतः विभागीय योजनाओं के युक्तिकरण एवम् विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विषेशज्ञ समिति बनाई जाएगी। MILKFED के माध्यम से 'National Dairy Plan-II' के अन्तर्गत प्रदेश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करके उसको implement किया जाएगा।

43. हिमाचल प्रदेश भेड़–बकरी पालकों का भी प्रदेश है। प्रदेश में 8 लाख भेड़ें तथा 11 लाख बकरियां हैं। भेड़ बकरियों के लिए FMD Vaccine, Deworming दवाई तथा अन्य दवाईयों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भेड़–बकरी पालकों की अन्य बड़ी समस्याओं में Dipping, Drenching की व्यवस्था में सुधार, ऊन कटाई की व्यवस्था में सुधार, उनके परम्परागत चरानों तथा रास्तों का समाप्त होना, भेड़–बकरी की ऊन के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आए बदलाव के कारण ऊन के

खरीद मूल्य में भारी गिरावट आदि है। मैं प्रदेश में भेड़–बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना **"भेड़–बकरी पालक प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना पर 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

44. प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक 'State Level Task Force' का गठन किया जाएगा जोकि 3 माह के भीतर इन पशुओं को किसानों तथा स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद समीप के गौ–अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं में रखने के लिए दिशा–निर्देश सुझाएंगे। इसी के साथ गौ–अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं के निर्माण तथा रख–रखाव से सम्बन्धित सुझाव भी दिये जाएंगे।

45. मैं निजि गौ–सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हज़ार 200 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

कृषि क्षेत्र के लिए कुल 582 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

बागवानी

46. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं 2024–25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की लागत से निम्न विकास कार्य पूरे करने की घोषणा करता हूँः–

- 75 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण।
- लगभग 1 हज़ार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में sub-tropical फलों के high density वृक्षों का रोपण कार्य किया जाएगा जिससे 80 कृषक समूहों के लगभग 6 हज़ार 500 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

- 12 करोड़ रुपये की लागत से एक **'बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र'** की स्थापना की जाएगी जोकि गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं के लिए 'One Stop Resource Centre' के रूप में कार्य करेगा।

- राज्य के Sub-tropical क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक **'Fruit Processing Unit'** स्थापित किये जाएंगे।

- 5 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद, नीम्बू तथा अन्य sub-tropical फलों को बढ़ावा देने के लिए mother trees/ bud wood banks के लिए **'Foundation Block'** की स्थापना की जाएगी।

47. बागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूँ कि 2024 के सेब सीज़न से universal carton का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु सचिव, कृषि की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।

48. प्रदेश में high return fruits जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लू बैरी, मैकाडामिया नट इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ वाई एस परमार बागवानी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार किये जाएंगे। इससे प्रदेश के किसानों की आय में शीघ्र एवम् निश्चित वृद्धि होगी।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटकों के बढ़ते हुए रूझान को देखते हुए Horticulture Tourism को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्थित बड़े बाग़ों तथा बाग़ों के समूहों को ग्रामीण पर्यटन की

दृष्टि से विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा। इस नीति के अन्तर्गत इच्छुक बागवानों को आवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

बागवानी के लिए कुल 531 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

मत्स्य पालन

50. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 13 हज़ार मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ✓ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिशत् उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- ✓ जिला हमीरपुर में 'Centre of Excellence' के रूप में एक नए 'Carp Fish Farm' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ नालागढ़ स्थित 'Fish Seed Farm' में 5 करोड़ रुपये की लागत से 'Brood Bank' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ प्रदेश के मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री–व्हीलर तथा ice-boxes उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- ✓ 10 नए 'Biofloc Fish Production' तालाबों तथा 10 नई लघु 'Biofloc Fish Production' इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
- ✓ तीन नई 'Feed Mills' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ दो बर्फ सयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

51. इसके अतिरिक्त प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में ट्राऊट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई ट्राऊट मछली उत्पादन इकाईयों तथा दो नई trout hatcheries की स्थापना की जाएगी।

ऊर्जा/बहुउद्देशीय परियोजनाएं

52. अध्यक्ष महोदय, गत् वर्ष भारी वर्षा के कारण अन्य सम्पत्तियों के साथ–साथ Larji Power House को लगभग 658 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। Larji Power House के Unit No. 1 को पूरी तरह से restore कर दिया गया है तथा अन्य दो यूनिटों को भी शीघ्र ही restore कर दिया जाएगा।

53. लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित होने वाले 'Himachal Pradesh Power Sector Development Programme' के लिए विश्व बैंक के साथ loan agreement sign कर लिया गया है। इसके माध्यम से Smart Grid Technology की सहायता से प्रदेश के 13 शहरों में 24X7 Power Supply सुनिश्चित करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

54. मैं, हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला 'हरित ऊर्जा' राज्य बनाने के अनुक्रम में तथा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- ❖ पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट का शिलान्यास 2 दिसम्बर, 2023 में किया गया था। मैं, इसे मार्च, 2024 तक के अंत तक commission करने की घोषणा करता हूँ।

- ❖ ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।

- ऊना के भंजाल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा।

- 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत् उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत, प्रथम चरण में, कुल 100 मैगावॉट सोलर क्षमता का दोहन सुनिश्चित किया जाएगा।

- निजी भूमि पर स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगावॉट सौर क्षमता का दोहन शीघ्र सम्पन्न हो पाएगा।

- प्रदेश के बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools' में ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' और Water Heating System स्थापित किये जाएंगे।

- सभी सरकारी भवनों के connected load के कम से कम 20 प्रतिशत् की आपूर्ति ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा।

- सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को NOC प्राप्त करने के लिए नए भवनों में 'Solar Water Heating System' लगाना अनिवार्य किया जाएगा तथा इन निगमों में स्थित सरकारी भवनों की छत पर चरणबद्ध तरीके से 'Solar Plant' लगाने होंगे।

- ऊना, काँगड़ा, सोलन, सिरमौर, मण्डी और शिमला ज़िलों में 501 मेगावॉट की क्षमता वाले 5 सौर पार्क और 212 मेगावॉट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

55. लगभग 1 हज़ार 885 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेशभर में Re-vamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के साथ–साथ Distribution Sector की Financial Sustainability भी बढ़ेगी।

56. बिजली उत्पादन के साथ–साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network होना समय की आवश्यकता है ताकि न केवल प्रदेश की जनता की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि surplus उत्पादन को उचित समय पर अन्य राज्यों को भी पहुँचाया जा सके। इसको और सुदृढ़ करने के लिए 2024–25 के लिए 96 करोड़ रुपये की लागत से चार transmission lines तथा 290 करोड़ रुपये की लागत से 6 Extra High Voltage (EHV) sub-station पूरे किये जाएंगे।

57. प्रदेश में स्थित transmission assets को National Grid से 'Central Transmission Utility System' के माध्यम से जोड़ा गया है। इसकी निरंतर monitoring के लिए कुनिहार में बन रहे 'Joint Control Centre (JCC)' तथा काँगड़ा के दैहन में sub-station के निर्माण का कार्य 2024–25 में पूरा कर लिया जाएगा। इससे transmission lines के शीघ्र रख–रखाव में भी सुविधा होगी।

58. अध्यक्ष महोदय, काँगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इसी क्रम में, 7 जुलाई, 2023 को काँगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Section 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए Rehablitation and Resettlement (R&R) Plan को

पर्यटन

शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त WAPCOS Ltd. द्वारा तैयार की गई मण्डी हवाई अड्डे की DPR का परीक्षण किया जा रहा है।

59. प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में 9 Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट; काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर; चम्बा में सुल्तानपुर; कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली; किन्नौर में शारबो; तथा लाहौल–स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में विकसित किये जाएंगे। इन 9 Heliports की feasibility study reports प्राप्त हो चुकी हैं; रक्कड़, सुल्तानपुर और पालमपुर का Obstacle Limitation Survey (OLS) हो चुका है और इनकी DPRs शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगी। रक्कड़ और पालमपुर का architectural design प्राप्त हो चुका है। 13 करोड़ रुपये प्रति हेलीपोर्ट की लागत से रक्कड़, पालमपुर, रिकाँग–पिओ, चम्बा में Heliports का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। दूसरे चरण में, चम्बा के पांगी और होली, बिलासपुर के औहर, सिरमौर के धारकियारी, शिमला के चाँशल धार, ऊना के जनकौर हर तथा सोलन के गलानाग में हेलीपोर्ट निर्मित किये जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से 'पवन हंस लिमिटिड' से आवश्यक सहायता ली जाएगी।

60. पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ते हुए स्वदेश दर्शन–2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया गया है। इसके साथ ही निम्न 5 Tourist Destinations को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगाः–

- लाहौल–स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी।
- किन्नौर में रकछम और नाको–चांगो–खाब।

61. मैं, कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge के निर्माण करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

62. पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा जिससे इनके संचालन में सुधार और गुणवत्ता लाई जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा

63. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या चिन्ता का विषय है। प्रदेश में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। मैं, 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में १०० करोड़ रुपये की लागत से State of the Art facilities के साथ **"State Cancer Institute"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। Indian Council of Medical Research (ICMR) की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा।

64. कैंसर पीड़ित मरीजों को प्रदेश में ही chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर **"Cancer Day Care Centres"** की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों में chemotherapy ले रहे सभी मरीजों के लिए beds का प्रावधान होगा तथा chemotherapy दवाओं को राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया जाएगा ताकि मरीजों को chemotherapy के लिए अधिक पैसा व्यय न करना पड़े।

65. Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से

उपचार के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से एक LINAC (Linear Accelerator) Machine स्थापित की जाएगी।

66. पिछले बजट में घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य केंन्द्रों पर कार्य विभिन्न चरणों में है तथा इनमें से अधिकांश का कार्य 2024–25 में पूरा कर दिया जाएगा तथा इसी वर्ष Machinery and Equipment की व्यवस्था करने के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

67. पिछले कई वर्षों से 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किये गए प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लम्बित environmental clearance दिलवायी गई। इसमें शुरू किये सभी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा।

68. प्रथम चरण में, प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना की जाएगी। इससे मरीज़ों को उनके digital record के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। इस क्रम में, लगभग 57 लाख प्रदेशवासियों का **'Aayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs'** बनाया जा चुका है तथा शीघ्र ही सभी पात्र प्रदेशवासियों का ABHA ID बना दिया जाएगा।

69. प्रदेश में Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत् मैं 1 करोड़ रुपये की लागत से **"State Level Scrub Typhus Research Unit"** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

70. Dr. Rajender Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में

नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centres' स्थापित किये जाएंगे। प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों में X-Ray की सुविधा नहीं है वहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए private practitioners के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

71. 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना की जाएगी।

72. पिछले बजट में घोषित नाहन, चम्बा और हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इसके साथ ही Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत किया जाएगा।

73. बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरम्भ किया जाएगा।

74. पिछली सभी सरकारों ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं आरम्भ की हैं। ऐसी ही योजनाओं में से 'हिमकेयर' तथा 'सहारा' 2019 में शुरू की गईं और इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुँचा है। किन्तु इनसे सम्बन्धित emperical data के analysis के बाद इनके कार्यान्वयन में कुछ structural तथा operational समस्याएं उजागर हुई हैं। इनमें से प्रमुख समस्या है कि convergence और technology की application के अभाव में कुछ योजनाओं में duplication हो रही है। मैं राष्ट्रीय स्तर

के domain experts की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा करता हूँ ताकि जरूरतमंद लोगों को उचित समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत् होता रहेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3 हज़ार 415 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

गुणात्मक शिक्षा

75. अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन–पोषण करेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। यह कथन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी गति और उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेजी से बदलती इस नई दुनिया में एक अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने में शिक्षा व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

76. यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी, समानता पूर्ण, future-oriented, नई तकनीक के प्रति सजग और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। हमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। भारत के संविधान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उद्देश्य तय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य इस पावन भावना के अनुरूप विभिन्नता में एकता एवम् बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है।

77. मेरी सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक स्वस्थ

जीवन दृष्टि विकसित करें तथा मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) के प्रयोग तक हर कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार प्रारम्भ किये हैं।

78. प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का सांझा प्रयोग आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं तथा इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इन संस्थानों में उचित गुणवत्ता और size के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, learning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playground, clean toilets के साथ–साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

79. आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सकें तथा आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोज़गार एवम् स्वरोज़गार प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषाएं सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गाँव के बच्चों को लाभ होगा।

80. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का pre-school 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी 6

हज़ार से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री–स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हज़ार Nursery Teachers नियुक्त किये जाएंगे। पात्र आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें Bridge Course भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुसार कम से कम 6 वर्ष की आयु तय की गई है और प्री–प्राईमरी की तीन कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है।

81. पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 'Institution of Excellence (IOE)' के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024–25 में, 850 शिक्षण संस्थानों को 'IOE' बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 500 प्राईमरी स्कूल 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेन्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ–साथ smart classrooms तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदण्डों के आधार पर इन संस्थानों का periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें इसके लिए स्कूल/कॉलेज Leadership प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

82. स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल–मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **''अपना विद्यालय–मेरा विद्यालय–मेरा सम्मान''** योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इसमें, जहाँ एक ओर मुख्य मन्त्री से लेकर खण्ड स्तरीय अधिकारियों तक सभी एक–एक शिक्षण संस्थान को

गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवम् इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

83. प्रत्येक उप–मण्डल में उप–मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी–बारी से अनिवार्य रूप से review meeting का आयोजन करना होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की performance का भी review किया जाएगा। अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख–रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

84. प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक Ranking और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरूआत की जाएगी। इस सारी व्यवस्था को Online Portal के माध्यम से विकसित किया जाएगा तथा इसे आम जनता तथा अभिभावकों से भी सांझा किया जाएगा जिसके लिए एक website बनाई जाएगी।

85. शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। अभी तक लिए गए निर्णयों में, वर्ष में कुल अध्यापन दिवस बढ़ाना, खेल एवम् सांस्कृतिक गतिविधियों का निश्चित समय तय करना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों में निरन्तर कमी करना, Mid Day Meal में रिकॉर्ड की औपचारिकताओं को कम करना शामिल हैं। अध्यापकों को विद्यालयों में भवन निर्माण कार्यों से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। एक ही सूचना को बार–बार मंगवाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह भी देखा गया है कि

आमतौर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगभग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था इस व्यवस्था पर भी पूर्णतः रोक लगाई गई है। अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो, इसके लिए विद्यालयों को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की वर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। आगामी वर्ष में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं, संरचना और नियमावली का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक बदलाव लाया जाएगा।

86. पढ़ने–पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024–25 में **''पढ़ो हिमाचल''** के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान में विद्यालयों के साथ–साथ ग्रामीण एवम् शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इसी अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए Reading Room बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।

87. मैं, प्रत्येक जिला व उपमण्डल मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूँ। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में, पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिस पर 88 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

88. शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है। अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा

State Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह प्रदेश में State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा।

89. जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग–अलग स्कूल अथवा महाविद्यालय चल रहे हों, स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकतानुसार उन दोनों को मिलाकर एक co-education शैक्षणिक संस्थान चलाने की शुरूआत की जाएगी। इससे छात्र व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के साथ–साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा तथा व्यक्तित्व उभरेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय न हो, वहाँ के बच्चों को नजदीक के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

90. अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार जल जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत को 49 अरब 78 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के दो तिहाई जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिले इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा तथा सरकारी स्कूलों के 8 लाख 50 हज़ार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

91. प्रदेश में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम का संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा। इसके लिए पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygiene तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। सभी विद्यालयों में खेलों तथा व्यायाम के

लिए प्रतिदिन कम से कम एक period अनिवार्य किया जाएगा। आवश्यकतानुसार Physical Education Teachers की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

92. 500 बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों को Mid Day Meal के अन्तर्गत भोजन बनाने और परोसने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

93. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) उच्च शिक्षा में प्रदेश की स्थिति को जाँचने एवम् इसमें किये जा रहे प्रयासों को आँकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024–25 में NAAC Accreditation के लिए प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी।

94. 2024–25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्त पोषण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 हज़ार 52 करोड़ रुपये तथा STARS Project के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त PM USHA के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तथा PM SHRI के तहत 477 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी।

95. पिछली सरकार ने प्रदेश में तीन स्थानों पर 'अटल आदर्श विद्यालय' बनाने प्रारम्भ किये हैं। मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए न केवल आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी बल्कि इन्हें क्रियाशील भी करेगी। 'राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों' तथा 'अटल आदर्श विद्यालयों' के लिए कर्मचारियों का एक विशेष संवर्ग बनाया जाएगा तथा इन्हें अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं, प्रथम चरण में, प्रदेश में पाँच राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहडू

और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

शिक्षा क्षेत्र में कुल 9 हज़ार 560 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

96. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोज़गार एवम् स्वरोज़गार अवसरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से market demand के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। मैं इसी अनुक्रम में निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा बगवां में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) में B.Tech और डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाएंगे।

- राजकीय बहुतकनीकी, सुन्दरनगर में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

- राजकीय बहुतकनीकी, हमीरपुर तथा तलवाड़ में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

- अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रगतिनगर में Civil Engineering के B.Tech और डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किये जाएंगे।

- राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से कक्षाएं आरम्भ कर दी जाएंगी।

97. श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर अभी तक 448 employers को जोड़ा जा चुका है। इसमें निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा तथा इसके माध्यम से 2024–25 में 180 campus interviews आयोजित किये जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20 लाख 87 हज़ार कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त श्रम एवम् रोज़गार विभाग की रोज़गार पंजीकरण पोर्टल को Common Service Centres (CSCs) के साथ भी link किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केन्द्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकें।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 330 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन

98. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 7 लाख 84 हज़ार लाभार्थियों के लिए लगभग 1 हज़ार 260 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। 2024–25 में 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

महिला एवम् बाल विकास एवम् कमज़ोर वर्गों का कल्याण

99. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। **'Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)'** को भी इस केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाएगा। इस केन्द्र में 0–27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की

सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

100. प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक **''आदर्श नशा निवारण केन्द्र''** की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र में पुस्तकालय, जिम, indoor तथा outdoor खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केन्द्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सिविल अस्पताल इस केन्द्र के आसपास हो जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ–साथ सम्बन्धित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक 'effective monitoring and reporting system' की स्थापना की जाएगी।

101. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इनके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों को समय पर उचित सुविधाएं पहुँचाने के लिए हमारी सरकार सदा से ही प्रयत्नशील रही है। मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे कृषकों एवम् वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों अथवा कोई पेंशन न ले रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

102. इसके साथ ही मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख–शिक्षा योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो, की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को medical college,

engineering college, NIT, IIM, IIT, Nursing, graduation/postgraduation पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता–पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

103. सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि 'जिला विकास समिति' की बैठक समय पर न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला के उपायुक्त को इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभों को स्वीकृत करने की शक्तियाँ दी जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में दी गई स्वीकृतियों पर जिला कल्याण समिति की होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

104. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे Post-Graduate Diploma in Computer Application तथा Diploma in Computer Application Courses में बाज़ार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD इत्यादि नए Courses को सम्मिलित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को उचित रोज़गार प्राप्त हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवम् अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हज़ार 457 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

105. अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से राशन, LPG गैस connections तथा सिलेंडर बिना किसी दाम के उपलब्ध करवाए गए। हमारी सरकार द्वारा की गई यह छोटी सी सहायता पीड़ित परिवारों के लिए संकट के समय में एक बड़ा सहारा बनी।

106. राशन डिपो के माध्यम से Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के मानदंडों के अनुसार विटामिन 'A' और 'D' से fortified सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी–विवाह, त्यौहार व अन्य समारोहों में उपभोक्ताओं को यह तेल खुले बाजार से ऊँचे दामों पर खरीदना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

107. Public Distribution System को और सुदृढ़ बनाने के लिए Integrated Management of Public Distribution System (IMPDS) को upgrade किया जाएगा तथा 'One Nation - One Ration Card (ONORC)' के अन्तर्गत National Portability को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे 'National Food Security Act (NFSA)' के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के अन्तर्गत Web आधारित KYC का प्रावधान किया जाएगा जिससे Inter State Portability के तहत लाभार्थियों को इस योजना के लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे। मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य उपदान के लिए कुल 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जाएंगे।

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

108. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष घोषित प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित किये जा रहे 'Plastic Waste Management Units (PWMU)' को 2024–25 में operationalize कर दिया जाएगा। इनके operations में backward और forward linkages सुनिश्चित की जाएगी ताकि इनका लाभ अन्य क्षेत्रों तथा समुदायों को भी मिल सके।

109. सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस मॉडल को convergence के माध्यम से अन्य पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से replicate किया जाएगा।

110. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 2024–25 में 5 हज़ार अतिरिक्त गाँवों को ODF+ (Open Defecation Free Plus) declare करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर कम से कम 4 sites पर Faecal Sludge Management Plants स्थापित किये जाएंगे।

111. 2024–25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हज़ार स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूहों को लगभग 32 करोड़ रुपये की धनराशि Revolving Fund तथा Community Investment Fund के रूप में देने के साथ–साथ इन्हें लगभग 50 करोड़ रुपये का ऋण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

112. सभी पंचायतों के accounts e-Gram Swaraj Software Application से जोड़ दिये गए हैं। इसके माध्यम से सभी पंचायतों के संसाधनों तथा व्यय की monitoring के लिए इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।

113. 2024–25 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 352 करोड़ रुपये 15वें वित्तायोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप तथा 448 करोड़ रुपये छठे राज्य वित्तायोग की सिफ़ारिशों के आधार पर व्यय किये जाएंगे।

114. पूर्व की UPA सरकार द्वारा आरम्भ किया गया 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (मनरेगा)' ग्रामीण बेरोज़गारों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मनरेगा कामगार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने के साथ–साथ public assets बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार प्रदेश सरकार मनरेगा कामगारों को 76 रुपये प्रतिदिन अपने संसाधनों से देगी। हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जोकि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को **''आत्मनिर्भरता''** की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ, ऐसी **''विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार''** जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हों, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी बशर्ते कि यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त न हुई हो।

115. मैं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- अध्यक्ष, जिला परिषद को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, जिला परिषद को 1,300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- अध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 11,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, पंचायत समिति को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- प्रधान, ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 800 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ौतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज के लिए कुल 2 हज़ार 356 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

शहरी विकास

116. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 से घर बनाने के लिए नक्शों की स्वीकृति AUTODCR के माध्यम से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी। यदि घर का नक्शा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पाई जाती है तो आवेदक उसे ऑनलाइन देखकर ही आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल

के माध्यम से private professionals 500 वर्गमीटर तक के आवासीय नक्शों की अनुमति भी दे पाएंगे।

117. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः–

- महापौर, नगर निगम को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- काउंसलर, नगर निगम को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- पार्षद, नगर परिषद को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- प्रधान, नगर पंचायत को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–प्रधान, नगर पंचायत को 1,100 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,600 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सदस्य, नगर पंचायत को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

118. शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबन्धन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना की जाएगी।

119. शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को digitalize किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक 'State Project Monitoring Unit' की स्थापना की जाएगी जोकि experts के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली की Online Planning, Implementation, Monitoring तथा Reporting में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अन्तर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवम् टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किये जा सकेंगे तथा विभिन्न certificate एवम् NOC ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। इसी के अन्तर्गत शहरी निकायों के accounts को digitize किया जाएगा। AGiSAC की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसम्पत्तियों की GIS mapping की जाएगी।

आवासीय सुविधा

120. अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना **''महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफ़ाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो तथा उनके पास अपना घर न हो, को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

121. मैं 'मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना' के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो, को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की

राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

122. नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को मकान आवंटित किये जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग तथा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

123. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल–जीवन मिशन तथा NDB और ADB के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। 2024–25 में किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 29 करोड़ रुपये की लागत से 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। New Development Bank (NDB) के माध्यम से 24 तथा Asian Development Bank (ADB) के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है तथा इन्हें तय समय–सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों के माध्यम से 20 हज़ार 663 परिवार Partially Covered (PC) Schemes से लाभान्वित होंगे तथा 79 हज़ार 282 परिवार Functional Household Tap Connection (FHTC) से लाभान्वित होंगे। **जल शक्ति**

124. शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से मैं, 2024–25 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- 4 शहरों क्रमशः ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ– पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता

वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।

- इसी प्रकार अंब और भुंतर के लिए 33 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024–25 के अंत तक इनका कार्य पूरा हो जाए।

- 112 करोड़ रुपये की लागत से नाहन, अर्की, निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

- मेरे पिछले बजट में घोषित 24X7 पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में रामपुर में वार्ड नं0 6 और 7, नालागढ़ और चम्बा में पेयजल योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

125. हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा की गई घोषणा को पूरा किया गया है तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से Village Water and Sanitation Committees का गठन करने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 69 Testing Labs स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 62 की accreditation, National Accreditation Board for Testing and Calibration द्वारा की जा चुकी हैं। 2024–25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवम् कीटाणु रहित पेयजल उपलब्ध हो सके।

126. पिछले बजट में घोषित SoP के अनुसार पेयजल योजनाओं तथा STP में UV System लगाने के लिए 37

ऐसी sites की पहचान की गई है जहाँ जल स्त्रोतों में या तो contamination है या इसकी सम्भावना है। इन sites पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से UV System लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

127. गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवाल्सर, भोटा, संतोखगढ़, बैजनाथ–पपरोला और नेरचौक में Sewerage परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी तथा उन्हें 2024–25 में पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे। राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा तथा शाहपुर में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024–25 में पूरा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त NABARD द्वारा स्वीकृत 16 ग्रामीण क्षेत्रों में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण के कार्यों को 2024–25 में ही अवार्ड कर दिया जाएगा। AFD द्वारा 817 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग तथा बिलासपुर के लिए Sewerage Treatment Plants (STP)/Waste Treatment Plants (WTP) और मनाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से मनाली Sewerage Network का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्यों को भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

128. 380 करोड़ रुपये की लागत से 14 Surface Minor Irrigation Schemes (SMISs) का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9 हज़ार 700 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध करवाया जाएगा। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि के आधार पर गति दी जाएगी। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत 4 योजनाओं में से लाबरंग गार्डन कालौनी तथा पूह के लिए स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिए लगभग

53 लाख रुपये की धनराशि Tribal Development Programme से उपलब्ध करवाई जाएगी।

129. 644 करोड़ रुपये की लागत से फिन्नासिंह बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना को सचिव, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) की अध्यक्षता में हुई Screening Committee की बैठक में 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana – Accelerated Irrigation Benefit Programme (PMKSY-AIBP)' के अन्तर्गत funding के लिए अनुशंसित किया गया है। इसके निर्माण से 4 हज़ार 25 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावॉट जलविद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। केन्द्र द्वारा जारी धनराशि के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी।

जल शक्ति के लिए कुल 3 हज़ार 365 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सड़कें एवं पुल

130. अध्यक्ष महोदय, मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों को व्यापक नुकसान पहुँचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गंवाये राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़कें traffic के लिए खोल दी गईं। छोटी सी अवधि में 18 Bailley bridges एवम् 27 Ropeway झूलों की सहायता से क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन–रात प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का कार्य किया, दिल से धन्यवाद करता हूँ।

131. रेलवे तथा जल परिवहन के अभाव में प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। पिछले लगभग 53 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बहुत सी नई सड़कें बनी तथा उनके माध्यम से बहुत से गाँव जुड़े। वर्तमान में 40 हज़ार 703 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 34 हज़ार 55 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 2 हज़ार 478 पुल हैं। कुल 3 हज़ार 615 ग्राम पंचायतों में से 3 हज़ार 578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष बची पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2024–25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

132. हमारी सरकार द्वारा 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना–।।।' के अन्तर्गत 2 हज़ार 683 किलोमीटर लम्बी 254 सड़कों के लिए 2 हज़ार 643 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 2024–25 में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये जाएंगेः–

- 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation.
- 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण।
- 8 पुलों का निर्माण।
- 15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- इस प्रकार 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना' के अन्तर्गत 825 किलोमीटर लम्बी सड़कों व 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना–। एवम् ।।' के अन्तर्गत 150 किलोमीटर लम्बी सड़कों में cross drainage.

133. हमारी सरकार द्वारा 2024–25 में 115 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 631 करोड़ रुपये के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 4 हज़ार 490 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को two Lane अथवा four Lane करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

- 500 करोड़ रुपये की लागत से सैंज – लूहरी – औट।
- 750 करोड़ रुपये की लागत से सैंज – लूहरी – औट राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर जलोड़ी पास सुंरग का निर्माण।
- 200 करोड़ रुपये की लागत से नगरोटा – बगवां – रानीताल।
- 300 करोड़ रुपये की लागत से चम्बा – भरमौर।
- 500 करोड़ रुपये की लागत से नाहन – कुम्हारहट्टी।
- लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर पुलों का निर्माण।
- लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य।

134. आगामी वर्ष के दौरान NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर cross-drainage,

425 किलोमीटर लम्बी सड़कों की tarring तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

135. Central Road Infrastructure Fund (CRIF) के अन्तर्गत निम्न 5 स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य 2024–25 में पूरा किया जाएगाः–

- जिया – मणिकर्ण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मुरम्मत कार्य।
- शाहपुर – सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग का उन्नयन।
- ब्यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण।
- बागछाल – मैहरे – बड़सर सड़क का उन्नयन।
- पंडोगा – तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।

136. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से 2024–25 में 230 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर plastic waste का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर Calcium Chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

137. 2024–25 में हमारी सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कें तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य पूरे किये जाएंगेः–

- ✓ 860 किलोमीटर लम्बी कुल सड़कों का निर्माण।
- ✓ 1 हज़ार 67 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर cross drainage.

- ✓ 1 हज़ार 75 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर metalling and tarring.
- ✓ 57 पुलों का निर्माण।
- ✓ 10 पंचायतों के 40 गाँवों को सड़क से जोड़ना।

सड़कों एवम् पुलों के लिए कुल 4 हज़ार 317 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

उद्योग/निजी निवेश

138. अध्यक्ष महोदय, बाज़ार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2019 में अधिसूचित ''औद्योगिक निवेश नीति'' में बदलाव करना अति आवश्यक है जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सभी स्वीकृतियाँ एक ही window के माध्यम से मिल जाए। इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हमारी सरकार 2024–25 में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई **''औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024''** लाएगी।

139. प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोज़गार की अनगिनत सम्भावनाएं हैं। युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 2024–25 में एक नई **''स्टार्ट–अप नीति, 2024''** लाने की घोषणा करता हूँ। इस नीति के अन्तर्गत innovation के लिए तथा महिलाओं को Start-Up Venture हेतु विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं द्वारा शुरू किये गए स्टार्ट–अप को एक वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

140. उद्योग क्षेत्र राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरी सरकार का प्रयास इस क्षेत्र को सर्वोत्तम eco-system प्रदान करना है। पिछले साल की आपदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर

बहाली कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से Electricity Duty (ED) की दर बढ़ायी थी। अब, जब स्थिति में सुधार हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ कि बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें 'हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019' के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक Electricity Duty (ED) का भुगतान करने में छूट दी गई थी।

141. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए गए हैं। 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी प्रदेश की खनन नीति में कुछ बदलाव किये जाने आवश्यक हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में **"Himachal Pradesh Mines and Minerals Policy, 2024"** लाई जाएगी जिसके मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना होंगे।

142. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से आग से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं के लिए अलग मानदण्ड तय किये जाएंगे। इन मानदण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या तथा किस्म के आधार पर chemicals, बिजली तथा अन्य कारणों से लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग–अलग SOPs तथा chemical protection suit, foam compound tank, dry chemical powder सहित अन्य उपकरणों और सामग्री का प्रावधान किया जाएगा।

143. बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश के संसाधनों तथा रोज़गार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं निवेशकों तथा कामगारों, दोनों के लिए आवश्यक हैं। मैं, इस क्षेत्र में 70 करोड़ रुपये की लागत से

शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। यह सड़क 'Medical Device Park' ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।

परिवहन

144. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 में 17 पैट्रोल पम्पों पर e-vehicle charging stations के साथ–साथ 'Indian Oil Corporation Ltd.' तथा 'राज्य विद्युत बोर्ड' की साझेदारी के साथ अन्य 33 पैट्रोल पम्पों पर 'e-vehicle charging stations' को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 55 अन्य सरकारी क्षेत्र के e-vehicle charging stations को कार्यशील कर दिया जाएगा।

145. 2023–24 में की गई HRTC की डीज़ल buses को electric buses से चरणबद्ध क्रम में बदलने की घोषणा के बाद अब तक HRTC के बेड़े में 110 electric buses और 50 electric taxis हो गई हैं। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में, 327 अतिरिक्त डीज़ल buses को electric buses से बदला जाएगा। इस पहल में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरूआती चरण में माननीय विधायकों से प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5 रूटों पर e-buses चलाने के लिए प्राथमिकताएं मांगी गई हैं।

146. 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana' के अन्तर्गत 2024–25 में 40 प्रतिशत् उपदान पर e-taxis चलाने के लिए 10 हज़ार permit दिये जाएंगे। हिमाचल को 'Green State' बनाने के प्रयासों के क्रम को जारी रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में वन विभाग, HRTC, HPTDC तथा GAD के eligible वाहन e-vehicle से बदल दिये जाएंगे।

147. धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाने हेतु प्रथम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा। प्रथम चरण में,

श्री अयोध्या धाम के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से 6 बसें चलाई गई हैं। 2024–25 में कुछ अतिरिक्त स्थानों से भी इस बस सेवा को चलाया जाएगा।

148. वर्ष 2024–25 में 'वाहन स्क्रैप नीति' के अन्तर्गत प्रदेश में **"Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** की स्थापना की जाएगी जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों को इसकी सुविधा मिल सके।

149. मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में Automated Testing Centres के माध्यम से सभी वाहनों की fitness अनिवार्य कर दी जाएगी ताकि वाहनों को fit declare करने में मानवीय गलती न हो।

150. परिवहन नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e-Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएंगी।

151. सभी परिवहन Barriers पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Cameras की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके। इस प्रणाली की सहायता से traffic को भी सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

152. 272 करोड़ रुपये की लागत से Nature Park, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच Hybrid Annuity Model (HAM) पर एक 3.2 किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इस रोपवे पर होने वाले लाभ का 50 प्रतिशत् अंश राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

153. लगभग 54 करोड़ की लागत से निर्मित किये जा रहे बगलामुखी रोपवे को हाल ही में आई आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ था जिसके कारण इसकी stabilization के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की

राशि व्यय की गई। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि इसका निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

154. हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line बिछाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी। इसी के साथ जेजों से पोलियाँ तक की rail line बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसके बिछने से प्रदेश में बन रहे 'Bulk Drug Pharma Park' तक रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 2024–25 में, इन दोनों रेललाईनों के सर्वे पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

वन

155. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Eco Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 93 Eco Tourism Sites को management and operation के लिए चरणबद्ध तरीके से outsource किया जाएगा। प्रथम चरण में, 13 Eco Tourism Sites को outsource करने के लिए 'Request for Proposal (RFP)' को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 2024–25 में इन सभी sites को outsource कर दिया जाएगा।

156. हमारी सरकार द्वारा की गई पहल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा working plans के आधार पर खैर की silviculture felling की अनुमति प्रदान की गई है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनको खैर के पेड़ काटने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा भी मिलेगी। 2024–25 में 10 Forest Divisions में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना तैयार की गई है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। माननीय न्यायालय के इस निर्णय से प्रेरित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काटने की अनुमति के

लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ–साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

157. 'हरित हिमाचल' की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किये जाएंगे। इन पार्कों को Eco-friendly materials के उपयोग से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इस हस्तक्षेप के माध्यम से muck sites को भी बहाल किया जाएगा।

158. अध्यक्ष महोदय, मैं वनों से सम्बन्धित सभी operations को Beat level पर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी 2 हज़ार 61 Forest Beats में एक–एक वन मित्र नियुक्त करने की घोषणा करता हूँ। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 2024–25 में पूरी कर ली जाएगी। Communities की सहायता से वनों के प्रबन्धन में इन वन मित्रों की अहम् भूमिका रहेगी।

159. इसी के साथ मैं 2024–25 में वन विभाग में Forests Guards के 100 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा करता हूँ।

वन विभाग के लिए कुल 834 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

160. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे green बनाने के लिए मैं **''मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृति योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत अगले 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गाँव चयनित किये जाएंगे तथा राज्य के Science Postgraduates तथा Engineering Graduates को उन गाँवों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृति दी जाएगी।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

161. हाल ही में हुई भारी वर्षा और जलवायु में निरंतर आ रहे बदलाव के दृष्टिगत् 2024–25 से जिला स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करने का काम आरम्भ किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।

162. 2024–25 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा GIZ के सहयोग से कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक **'Need Assessment Study (NAS)'** शुरू की जाएगी।

163. प्रदेश में अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ की जाएगी जिसकी सहायता से प्रदेश में हो रही mining गतिविधियों की real time निगरानी की जाएगी।

164. प्रदेश में Geographical Indications (GI) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरम्भ की जाएगी जिसके माध्यम से commercial products की GI tagging की जाएगी ताकि उत्पादकों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

डिजीटाइजेशन, गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Governance को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में 2024–25 के दौरान निम्न कदम उठाने की घोषणा करता हूँः–

- ✓ प्रदेश में Artificial Intelligence (AI) के साथ–साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए एक work plan बनाकर इस दिशा में शुरूआत की जाएगी।

- ✓ 'Online Sewa Portal' के माध्यम से पहले से उपलब्ध ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को और प्रभावी ढंग से प्रदेशवासियों तक पहुँचाने के लिए एक mobile app आरम्भ की जाएगी।

- ✓ हिमाचल प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों, सभी DC एवम् SP कार्यालयों और 253 field कार्यालयों में e-office का सफल कार्यान्वयन करने के बाद इसके माध्यम से सभी कार्यालयों में ई–हस्ताक्षर की सुविधा के साथ–साथ ऑनलाइन e-dispatch की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- ✓ CM-Dashboard को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों को Reporting Management Portal के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभागों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

- ✓ 'मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प' हेल्पलाइन में Artificial Intelligence का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिकायतों का कम से कम समय में निवारण किया जा सके।

- ✓ गत् वर्ष विकसित किये गए DBT Portal को 'National DBT Portal' के साथ जोड़ा जाएगा जिससे दोनों Portals की सूचना को साझा किया जा सके।

- ✓ निवेशकों द्वारा किये गए 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को

आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट किया जाएगा।

- ✓ State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसमें उपलब्ध data और अन्य सूचना की सुरक्षा के लिए नवीनतम उपाय किये जाएंगे।

- ✓ हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि प्रदेशवासियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ कम से कम समय में मिल सके।

भू–प्रशासन, सुधार

166. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 से 'मेघ–जमाबंदी' के अन्तर्गत कोई भी नागरिक किसी भी समय ज़मीन से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रतियाँ download कर सकेगा। इसी पोर्टल पर UPI/Debit Card/Credit Card इत्यादि के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

167. 'मेघ–चार्ज' के अन्तर्गत 'Kisan Credit Card' ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके माध्यम से बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों तथा तहसील कार्यालयों में बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी औपचारिकताएं इस एकीकृत module के माध्यम से पूरी करके बहुत कम समय में ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

168. सम्पत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान मेघ–पंजीकरण module के माध्यम से आरम्भ किया जाएगा। इसी

तरह मेघ–म्यूटेशन module के उपयोग से ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

169. बहुत से भू–अभिलेखों का वर्णन कठिन शब्दों में उपलब्ध है। इन भू–अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त संशाधन

170. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पिछले बजट में घोषित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों के अनुक्रम में मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ❖ करदाताओं की सुविधा के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए 2024–25 में एक 'Mobile App' की शुरूआत की जाएगी। इस App के प्रयोग से करदाता ऑनलाइन कर भुगतान कर सकेंगे।

- ❖ प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से **'करदाता संवाद अभियान'** आरम्भ किया जाएगा इससे प्रदेश की कर एवम् आबकारी प्रणाली को और सरल तथा पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।

गृह/कानून व्यवस्था

171. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस–पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा।

172. अध्यक्ष महोदय, पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

मैं, पुलिस कर्मियों को वर्तमान में दी जा रही 210 रुपये की डाइट मनी को लगभग 5 गुणा बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। इस प्रकार पुलिस कर्मियों को लगभग 9 हज़ार रुपये से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होगा। इससे लगभग 18 हज़ार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। इससे 16 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक व्यय होंगे।

173. अगले 5 वर्षों में, प्रदेश की 1 प्रतिशत् जनता को 'Civil Defence Scheme' के अन्तर्गत लाया जाएगा। यह पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

174. अग्निशमन से सम्बन्धित NOC देने तथा उसे withdraw करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'Himachal Pradesh Fire Fighting Services Rules' अधिसूचित किये जाएंगे।

175. मैं, 2024–25 में, काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खोलने की भी घोषणा करता हूँ।

खेल एवं युवा सेवाएं

176. प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़–चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024–25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अन्तर्गत मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूँः–

- ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तथा

कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- एशियन खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।

- कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी।

- राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier किराया दिया जाएगा। तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare दिया जाएगा।

- सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

- मैं विभिन्न स्तरों की प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ौतरी करने के बाद निम्न की घोषणाएं करता हूँः–

  - प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

177. अध्यक्ष महोदय, मैं 2024–25 में निम्न खेल परिसरों के निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा करता हूँः–

- ❖ हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ रैहन में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ❖ खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

सूचना एवं जन सम्पर्क

178. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए एक favourite destination बनाने के उद्देश्य से 2024–25 से हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर एक 'Film Development Council' का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में 'Film Facilitation Cell' की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना की जाएगी।

179. सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न web channels, news websites और Social Media Influencers के माध्यम से प्रसारित एवम् प्रचारित करने के लिए 'Digital Media Policy, 2024' का कार्यान्वयन किया जाएगा।

180. सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना को 'हिमसूचना कोष' Data App के माध्यम से संकलित किया जाएगा जिससे कि प्रकाशन

के लिए तथा प्रैस में देने योग्य सूचना को तुरन्त ही प्राप्त करके प्रैसनोट अथवा लेख प्रिंट किये जा सकें।

सैनिक कल्याण

181. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युद्ध तथा शांति के समय में प्रदेश के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवम् शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा दी गई सेवाएं तथा उनके बलिदान के लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी।

182. मैं घोषणा करता हूँ कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जिनको और कोई पेंशन नहीं मिलती है, को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा।

183. हमारी सरकार 2024–25 में सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

सहकारिता

184. अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले बजट में घोषित प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की computerization के अनुक्रम में इन्हें सहकारी बैंकों, सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय database से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे तय समय सीमा 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

मानदेय वृद्धि

185. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँः–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

- मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 400 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 7,000 रुपये मिलेंगे।

- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी की जाएगी।

- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत चौकीदार को 1,000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व चौकीदार को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व लम्बरदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- IT Teachers को 1,900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

विधायक प्राथमिकताएं

186. प्रत्येक वर्ष की भाँति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ✓ शिमला विधानसभा चुनाव क्षेत्र शहरी क्षेत्र होने के कारण नाबार्ड के RIDF के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की स्वीकृति हेतु पात्र नहीं है। यही समस्या धर्मशाला, मण्डी, सोलन तथा पालमपुर नगर निगमों में पड़ने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भी आने वाली है। मैं इन पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृत करवाने की घोषणा करता हूँ।

- ✓ हमारी सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के संकल्प के अनुक्रम में, मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 से विधायक प्राथमिकताओं के

स्वरूप में भी परिवर्तन करने की घोषणा करता हूँ। अब माननीय विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की तीन वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से एक प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रख–रखाव से सम्बन्धित दी जा सकेगी। पाँचवी प्राथमिकता HRTC के वर्तमान रूट पर electric bus चलाने तथा आवश्यक charging stations से सम्बन्धित होगी।

- ✓ Overhead बिजली की तारों तथा अधूरे 'मुख्य मन्त्री लोक भवनों' का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मन्त्री आवास योजना' के दिशा–निर्देशों के अनुरूप यदि माननीय विधायक किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशंसा करना चाहे तो वे इस निधि से कर पाएंगे।

- ✓ इसी के साथ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर, 175 करोड़ रुपये से 195 करोड़ रुपये करने की भी मैं घोषणा करता हूँ। प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि में से प्राथमिकताएं electric buses चलाने तथा charging stations से सम्बन्धित होंगी।

- ✓ 'विधायक ऐच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।

- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि को 2 करोड़ 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

187. अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत कार्यों को शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है, जोकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया में हर साल नए कार्य शुरू होते हैं जबकि पहले से चल रहे कार्य संसाधनों की कमी के कारण रूक जाते हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मैं घोषणा करता हूँ कि चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 2024–25 में कम से कम 1 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब हैं। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जा रहा है।

कर्मचारी कल्याण

188. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ की महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर्ज़ के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी व पेंशनर्ज़ बहनों और भाईयों को भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

189. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं, निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- सभी कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

- 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

- मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत् की दर से मँहगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

- प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक बार All India Leave Travel Concession (LTC) ले सकते हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा ले पाएंगे।

- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

- आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हज़ार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हज़ार 500 किया जाएगा।

हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा।

बजट अनुमान

190. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2023–24 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 40 हज़ार 446 करोड़ रुपये हैं। 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45 हज़ार 926 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5 हज़ार 480 करोड़ रुपये का राजस्व deficit अनुमानित हैं।

191. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के लिए 58 हज़ार 444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

192. वर्ष 2024–25 में राजस्व प्राप्तियाँ 42 हज़ार 153 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46 हज़ार 667 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4 हज़ार 514 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 हज़ार 784 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत् है।

193. 2024–25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 25 रुपये, पैंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 28 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

194. अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु **अनुबन्ध** में दर्शाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द – जय हिमाचल

बजट सांराश

बजट के मुख्य बिन्दु

- **58 हज़ार 444 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।**
- **2023–24 के दौरानः–**
  - **प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत्।**
  - **प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हज़ार 199 रुपये अनुमानित।**
  - **राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये अनुमानित।**
- **'आत्मनिर्भर हिमाचल'**
- समृद्ध किसान हिमाचल
- हरित और स्वच्छ हिमाचल
- बिजली राज्य हिमाचल
- पर्यटन राज्य हिमाचल
- कुशल और दक्ष हिमाचल
- स्वस्थ एवम् शिक्षित हिमाचल
- निवेशक मित्र हिमाचल
- नशा मुक्त हिमाचल
- अवैध खनन मुक्त हिमाचल
- समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

1. समृद्ध किसान हिमाचल

- ✓ किसानों को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत रोज़गार के अवसर तथा आय में वृद्धि।
- ✓ बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गये गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

- ✓ 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
- ✓ 'हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन' के अन्तर्गत 2 हज़ार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में high value फसलों को बढ़ावा।
- ✓ मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना।
- ✓ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण।
- ✓ सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार; कुल्लू में चौरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू; मण्डी में टकोली और कांगनी; काँगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर; तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन।
- ✓ किसानों की सुविधा के लिए Chat Bot और AI पर आधारित भू–अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के database सहित एक web आधारित कृषि पोर्टल और Mobile App बनाया जाएगा।
- ✓ सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक **'Centre of Excellence Hi-Tech Vegetable Nursery Production'** खोला जाएगा।
- ✓ पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी।
- ✓ 'हिम–गंगा' योजना के अन्तर्गत काँगड़ा के ढगवार में 1.5 LLPD (Lakh Litre Per Day) की क्षमता वाले **'Fully Automated Milk and Milk Products Plant'** की स्थापना।
- ✓ ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'Milk Processing Plants' स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ स्थानीय युवाओं को दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत् उपदान पर 200 refrigerated milk vans उपलब्ध।

- ✓ सोलन जिले के दाड़लाघाट में **'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र'** की स्थापना।

- ✓ प्रदेश में भेड़–बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए **"भेड़–बकरी पालक प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ।

- ✓ 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ।

- ✓ बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक 'State Level Task Force' का गठन किया जाएगा।

- ✓ निजि गौ–सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये।

- ✓ एक **'बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र'** की स्थापना। जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित आवश्यकताओं हेतु 'One Stop Resource Centre' के रूप में कार्य करेगा।

- ✓ राज्य के Sub-tropical क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक **'Fruit Processing Unit'** स्थापित किये जाएंगे।

- ✓ अमरूद, नीम्बू तथा अन्य sub-tropical फलों को बढ़ावा देने के लिए mother trees/ bud wood banks के लिए **'Foundation Block'** की स्थापना की जाएगी।

- ✓ 2024 के सेब सीज़न से universal carton का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा।

- ✓ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिशत् उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

- ✓ जिला हमीरपुर में 'Centre of Excellence' के रूप में एक नए 'Carp Fish Farm' की स्थापना।

- ✓ मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री–व्हीलर तथा ice-boxes उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- ✓ 10–10 नए 'Biofloc Fish Production' तालाबों तथा इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
- ✓ तीन नई 'Feed Mills' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ 150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाईयों सहित नई trout hatcheries की स्थापना की जाएगी।

2. हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल

- ✓ पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट को मार्च, 2024 तक के अंत तक commission किया जाएगा।
- ✓ ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनकर तैयार।
- ✓ ऊना के भांजल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण।
- ✓ 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत् उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति।
- ✓ बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और Rajiv Gandhi Day Boarding Schools में ग्रिड से जुड़े Roof Top Solar Plant और Water Heating System स्थापित।
- ✓ Re-vamped Distribution Sector Scheme के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन।
- ✓ बिजली उत्पादन के साथ–साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network के लिए चार transmission lines तथा 6 EHV sub-station पूरे किये जाएंगे।
- ✓ 327 अतिरिक्त डीज़ल buses को electric buses से बदला जाएगा।
- ✓ 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana' के अन्तर्गत 40 प्रतिशत् उपदान पर e-taxis चलाने के लिए 10,000 permit दिये जाएंगे।

- ✓ वन विभाग, HRTC, HPTDC के सभी तथा GAD के पात्र वाहन e-vehicle से बदल दिये जाएंगे।
- ✓ 'वाहन स्क्रैप नीति' के अन्तर्गत प्रदेश में **"Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** की स्थापना।
- ✓ 'हरित हिमाचल' की दिशा में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किए जाएंगे।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे green बनाने के लिए **''मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृति योजना''** आरम्भ।
- ✓ कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक **'Need Assessment Study (NAS)'** शुरू।
- ✓ Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन।

३. <u>पर्यटन राज्य हिमाचल</u>

- ✓ काँगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Rehablitation and Resettlement (R&R) Plan को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
- ✓ पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा।
- ✓ १६ प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में ९ Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट; काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर; चम्बा में सुल्तानपुर; कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली; किन्नौर में शारबो; तथा लाहौल–स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में।
- ✓ कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge.
- ✓ Nature Park, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच Hybrid Annuity Model (HAM) पर एक ३.२ किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ।

- ✓ स्वदेश दर्शन–2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया जाएगा।
- ✓ लाहौल–स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी तथा किन्नौर में रकछम और नाको – चांगो – खाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
- ✓ पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line तथा जेजों से पोलियाँ तक की रेललाईन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध।

4. <u>स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवम् दक्ष, हिमाचल</u>

- ✓ 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में आधुनिकतम diagnostic तथा treatment facilities के साथ 'State Cancer Institute' की स्थापना।
- ✓ कैंसर पीड़ित मरीजों को chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर **"Cancer Day Care Centres"** की स्थापना।
- ✓ Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से उपचार के लिए LINAC (Linear Accelerator Machine) स्थापित।
- ✓ 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति।
- ✓ 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना।
- ✓ Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत् मैं 'State Level Scrub Typhus Research Unit' स्थापित।
- ✓ Dr. Rajinder Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centres' स्थापित।
- ✓ प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना।

- ✓ Dr. Rajindra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत।
- ✓ बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरम्भ।
- ✓ 'हिमकेयर' तथा 'सहारा' योजनाओं के कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर के domain experts की सहायता से आवश्यक सुधार।
- ✓ प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उचित गुणवत्ता और size के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, leaning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playground, clean toilets के साथ–साथ अन्य सभी सुविधाएं।
- ✓ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का pre-school 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल।
- ✓ शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 'Institutions of Excellence' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ✓ स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल–मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **''अपना विद्यालय–मेरा विद्यालय–मेरा सम्मान''** योजना प्रारम्भ।
- ✓ प्रत्येक उप–मण्डल में उप–मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी–बारी से अनिवार्य रूप से review meeting.
- ✓ सभी शिक्षण संस्थाओं की वार्षिक Ranking और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरूआत।
- ✓ पढ़ने–पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में **''पढ़ो हिमाचल''** के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ।
- ✓ शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा State

Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन।

- ✓ सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ✓ पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygine तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ।
- ✓ प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपमण्डल तथा पंचायत मुख्यालय पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय।
- ✓ पाँच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहडू और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ।
- ✓ श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा तथा 2024–25 में 180 campus interviews आयोजित किये जाएंगे।

5. निवेशक मित्र हिमाचल

- ✓ किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
- ✓ शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना।
- ✓ ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ– पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- ✓ नाहन, अर्की निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ।
- ✓ 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation, 325 किलोमीटर नईं सड़कों तथा 8 पुलों का निर्माण।
- ✓ 15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

- ✓ NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर cross-drainage, 425 किलोमीटर लम्बी tarred सड़कों तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ CRIF के अन्तर्गत 5 स्वीकृत सड़कों, जिया – मनीकरण सड़क, शाहपुर – सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग तथा बागछाल – मैहरे – बड़सर का उन्नयन, यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल तथा पंडोगा तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।
- ✓ अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर calcium chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
- ✓ एक नई **''औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024''** आरम्भ।
- ✓ युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई **''स्टार्ट–अप नीति, 2024''** आरम्भ।
- ✓ बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें 'हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019' के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक ED का भुगतान करने में छूट दी गई थी।
- ✓ शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाई जाएगी जो 'Medical Device Park' ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।
- ✓ हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन।
- ✓ सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में 'Film Facilitation Cell' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना।
- ✓ पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति।

6. नशा मुक्त हिमाचल

- ✓ राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक **''आदर्श नशा निवारण केन्द्र''** की स्थापना।
- ✓ उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक 'effective monitoring and reporting system' की स्थापना।
- ✓ हमीरपुर तथा ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ रैहन और देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये।
- ✓ एशियन खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।
- ✓ कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- ✓ टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि।
- ✓ राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier

किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare।

- ✓ सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
- ✓ प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

7. अवैध खनन मुक्त हिमाचल

- ✓ सभी परिवहन Barriers पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Cameras की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।
- ✓ करदाताओं की सुविधा के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए 'mobile app' की शुरूआत।
- ✓ प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से 'करदाता संवाद अभियान' आरम्भ किया जाएगा।
- ✓ अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ।

8. समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

- ✓ वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित।

- ✓ दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** की स्थापना। इसमें आवासीय सुविधाओं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाओं सहित पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- ✓ 0–27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं।
- ✓ **"Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)"** को **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** में स्थानान्तरित।
- ✓ नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना''** आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
- ✓ एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख–शिक्षा योजना''** आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी।
- ✓ विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता–पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।
- ✓ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाज़ार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD इत्यादि नए Courses.
- ✓ वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना **''महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना''** आरम्भ।
- ✓ मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी। विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
- ✓ 'मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना' के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये।

- ✓ नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
- ✓ Artificial Intelligence (AI) के साथ–साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए work plan की शुरूआत की जाएगी।
- ✓ निवेशकों द्वारा किये गए 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट।
- ✓ State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- ✓ हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा।
- ✓ ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e-Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएंगी।

९. कर्मचारी, पैरा वर्कर्ज़, मनरेगा कामगार, तथा अन्य वर्गों का कल्याण

- ✓ कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।
- ✓ 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।
- ✓ 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत् की दर से मँहगाई भत्ते की किश्त जारी।
- ✓ 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा।
- ✓ दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

- ✓ आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हज़ार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हज़ार 500 किया जाएगा।
- ✓ बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपये मासिक, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये, आशा वर्कर को 5,500 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 4,500 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,000 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 6,300 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 12,000 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये, IT Teachers को 1,900 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।
- ✓ पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों के मानदेय में 4,000 रुपये, उपाध्यक्षों के 3,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद के 1,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति के 1,900 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1,400 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति के मानदेय में 1,200 रुपये, प्रधान के मानदेय में 1,200 रुपये व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि।
- ✓ स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000 रुपये, उप–महापौर नगर निगम के मानदेय में 3,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम के मानदेय में 1,400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,700 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,400 रुपये, पार्षद नगर परिषद के मानदेय में 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपये, उप–प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपये एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि।

- ✓ सभी 2 हज़ार 61 Forest Beats में एक–एक वन मित्र की नियुक्ति।
- ✓ वन विभाग में Forests Guards के 100 रिक्त पदों की भर्ती।
- ✓ पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1,000 रुपये की गई।

10. अन्य

- ✓ सभी वाहनों की Fitness, Automated Testing Centres के माध्यम से अनिवार्य।
- ✓ बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष में इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
- ✓ खैर की silviculture felling से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि। 10 Forest Divisions में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- ✓ माननीय न्यायालय से चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ–साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
- ✓ भू–अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र शुरू।
- ✓ शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस–पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं।
- ✓ काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन।
- ✓ निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खुलेंगी।
- ✓ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- ✓ 'विधायक ऐच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।
- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि 2 करोड़ 20 लाख रुपये।
- ✓ 2024–25 में 1 हज़ार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।

******

Honourable Speaker Sir,

With your permission, I present the budget estimates for the year 2024-25.

1. Due to unprecedented rains in the State last year, many people of the State lost their lives. May all the departed souls rest in peace and I express my heartfelt condolences to their families on behalf of the State Government and this August House. Due to this rain, there has been widespread loss of life and property in the State, which may take time to get compensated.

2. This is the second budget of our Government. While presenting last year's budget, I had said that public service requires **'good Government'** along with '**good governance'**, and that we must bring changes in every sector as per the requirement of changing time. We have initiated this change. As soon as my Government assumed charge, the Old Pension Scheme was restored. 1,15,000 employees have already opted for OPS. All the employees who have come to OPS have received the General Provident Fund (GPF) subscription. About 5,000 employees who have shifted from NPS to OPS, have been issued Pay and Pension Orders (PPOs) as per the OPS after their retirement. A 'Start-up Yojana' worth Rs.680 crore has been started for the youth. Its two components i.e. 'Rajiv Gandhi Swarozgar Yojana' with a provision of 50 percent subsidy for e-taxis and 'Rajiv Gandhi Start-up Yojana' with a provison of 50 percent subsidy for solar panels with capacity upto 500

KW have already been rolled out. The third component finds a mention in this speech. Our Government has started disbursing an increased pension of Rs.1,500 from Rs.1,150 per month to about 2.37 lakh women in the State. Additionally, all the women in Lahaul & Spiti have started getting a monthly pension of Rs.1,500 from the current financial year. We will fulfil the promises made before the elections, to the people of the State in a phased manner, but we must understand that the old rules, laws and procedures cannot help in fulfilling these promises. Government must bring changes in its organisation, structure, technology and conduct to meet present and future challenges. The State Government has started the process of making multidimensional and fundamental changes with this intent during the past one year. Positive results of these changes have started emerging. This **'Vayvastha Parivartan'** will not only continue but will also be given pace.

3. The concept of good Government and good governance cannot be realized in the 21st Century by following old ideas of the old institutions. While entering the fifth year of the second decade of the 21st Century, we need to think in the context of the current situation prevailing across the world.

4. Speaker Sir, you will agree that all the conflicts, wars and burning issues of the world also impact the lives of the common people of Himachal Pradesh in one way or another. Be it the Israel-Palestine conflict in the Gaza Strip or Ukraine war, they have affected the economy of our country and State directly or indirectly.

5. Although, change in circumstances and opportunities is a continuous process, every change has its own peculiarity. In the present time, while on one hand there are challenges like rising average temperature of the planet and its adverse effects, on the other hand, there are immense possibilities of bringing betterment through ethical use of disruptive technologies. Our Government will seriously work on the available opportunities through the use of Artificial Intelligence (AI). Inclusive development and public welfare will be ensured with its help, which will accelerate our journey towards '**self-reliance'** of the State.

6. Speaker Sir, the path of development is difficult, there are obstacles to it, but we will not let any obstacle come in the way of development. Good governance is the ability to take tough decisions in challenging times. My Government is capable of dealing with any situation. We have demonstrated this capability during last year's natural disaster. Along with the praise done by the NITI Aayog and national magazines, the relief work done by our Government has also been appreciated by the World Bank.

7. Our Government changed the Relief and Rehabilitation Rules that had been in place for years and released a Special Relief Package of Rs.4,500 crore as a measure of relief to the disaster affected. It is noteworthy that the State Government did not receive any special relief package from the Centre despite the unprecedented natural disaster. But still we set our priorities at the State level and provided as much assistance as possible to every affected person. We

increased the amount given for reconstruction of completely damaged houses from Rs.1,30,000 to Rs.7 lakh, which is an unprecedented increase. Similarly, the compensation for partial damage to a kutcha house has been increased from Rs.6,000 to Rs.1 lakh. The financial assistance given on loss of shops and dhabas has been increased four times from Rs.25,000 to Rs.1,00,000 and the relief given on loss of cow sheds has been increased from just Rs.3,000 to Rs.50,000. Not only this, we have provided an amount of Rs.5,000 per month in rural areas and Rs.10,000 per month in urban areas for the disaster affected families to rent houses. With the help of this increased assistance amount, 2,968 beneficiaries were provided assistance for completely damaged houses, more than 10,000 beneficiaries were provided assistance for repairing partially damaged houses, 3,648 beneficiaries were provided assistance for Gaushalas and about 1,800 beneficiaries were provided assistance in the form of compensation for the loss of livestock. Apart from this, about 2,600 farmers were provided assistance for the damage caused to their crops and land and assistance was provided for the repair of 507 shops and dhabas. Our Government provided immediate relief assistance to 22,130 beneficiaries. The Government will be providing food and water to the disaster affected families till 31st March, 2024. This has happened for the first time in the history of the State. This, probably is the most liberal assistance given by any Government in the entire country in the event of a disaster.

8. Our Government has come to power only and only for the welfare of people of the State. I have

repeatedly said that we have come to power not to enjoy the power but to change the destiny of the State. We are working keeping in mind the long-term interests of every citizen of the State. The neglected, deprived, and marginalized people of the society are at the top priority for us.

9. 'Mukhya Mantri Sukh Ashraya Yojana' is an example of our intent and policy of my Government for the welfare of the last person of the society, under which more than 4,000 children have been adopted as 'Children of the State'. I wish to give a message to every citizen of the State through this scheme that our Government will always stand with people of the State and shall work relentlessly for their welfare.

10. Speaker Sir, the job of the Government is to build people's relationship with the Government in their everyday lives. It has to work to simplify rules, procedures and make Government services available at doorsteps, so that the common person does not have to visit offices and face difficulties due to complex procedures. We have started organizing special courts in the Revenue Department for early settlement of land related matters. 89,091 mutation cases and approximately 6,000 partition cases have been settled in these special courts which were pending for many years. All the processes related to Forest Clearances were simplified to speed up the pace of development works. As a result, in the last one year, in-principle approval was obtained on 58 proposals related to hydropower and other projects which were pending for more than 10 years and the final approval of the Government of India was obtained on 71 proposals

related to forest clearance. The Government challenged the decision given by the NGT staying 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' in the Hon'ble Supreme Court. Due to our efforts, the Hon'ble Supreme Court overturned the decision of the NGT and upheld 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' which has brought relief to the residents of Shimla. Due to this historic decision, the work for building a modern township in Jathia Devi will also get momentum.

11. My Government has set a target of making the State a 'Green Energy State' by 31st March, 2026. Himachal Pradesh is the leading State in the country to take initiatives from this perspective. We have established 6 'green corridors' in the State. Himachal Pradesh has signed an MoU for Green Hydrogen and Ammonia Project which will entail an investment of Rs.4,000 crore and provide employment to more than 3,500 people of the State. The Government has decided to provide 50 percent subsidy on purchase of electric vehicles to Himachali youth to promote electric vehicles,. There is a great enthusiasm among the youth about this scheme. Similarly, solar energy projects, Roof Top Solar Plants and non-conventional energy-based investments are being specially promoted.

12. Himachal Pradesh used to be known as the 'power State of the country' till a few years ago, but due to the wrong policies adopted in the past, there has been a decrease in the enthusiasm to set up new power projects on one hand and on the other hand, the contracts signed by the previous Governments are not favourable to the interests of the State. There is a need

for further reforms and changes in these policies. Green energy is the future of the country and the world. We must move forward in this direction. There are immense possibilities for investment and employment in this sector. My Government is committed to developing this sector on priority.

13. Speaker Sir, change in the system is the need of the hour. It is an imperative for any society to choose the right path as per the prevailing circumstances for progress. History is witness to the fact that whenever there is a need for major change, traditional methods need to be replaced with new ones. These cause disruption for a brief period of time. But this disruption is temporary and results start showing after this. Today's circumstances are demanding the same from the leadership of Himachal Pradesh. I am confident that we all will convert the challenges of the day into opportunities and with the help of this change, we will move towards **'self-reliance'** by writing the story of a rich and prosperous Himachal.

14. Speaker Sir, it in the backdrop of above points that our Government has envisioned the following for a prosperous and '**self-reliant'** Himachal in the coming 10 years:

- **'Self-reliant Himachal'**
- Prosperous Farmer Himachal
- Green and Clean Himachal
- Electricity State Himachal

- Tourism State Himachal
- Skilled and Innovative Himachal
- Healthy and Educated Himachal
- Investor Friendly Himachal
- Drug Free Himachal
- Illegal Mining Free Himachal
- Prosperous Himachal

15. This is the vision of a prosperous, culturally rich, healthy, capable, strong and **'Aatam Nirbhar Himachal'**. Energetic youth and empowered women of the State will take a lead in bringing this change. This is a picture of a Himachal in which at one end, the farmer families will get increase in income due to the initiatives of integrated development through agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries and allied sectors at the village level, while at the other end, young men and women; educated, skilled and proficient in modern technology will bring positive changes in the State, country and the world. We have to work for building end to end eco-system to realize the dream of agriculture and milk production based '**Aatam Nirbhar'** economy at the local rural level and with the use of modern technology, we must build an eco-system to ensure sustainable growth. Through this budget, I am presenting the draft for realizing the vision of **'Aatam Nirbhar Himachal'**. The process of bringing all necessary changes and structural reforms in the economy of the State will be completed by 2027. The positive results of

these reforms will start flowing concurrently, with which the process of realizing the vision of **'Aatam Nirbhar Himachal'** by 2032 will begin.

16. The adverse financial situation that our Government inherited from the previous Government is known to everyone. Our Government is facing many challenges due to financial mismanagement and wasteful expenditure spree practised by the previous Government. Due to wrong policies in the past, total liabilities in the form of loans have risen to Rs.87,788 crores. Total debt liabilities have increased from Rs.47,906 crore in 2018 to Rs.76,651 crore in 2023. The previous Government implemented the Sixth Pay Commission recommendations for Himachal Government employees at the end of its tenure, which could have been implemented earlier. Due to this delay, the arrears on account of the revised salaries of the employees kept increasing and their liabilities were handed over to our Government. But the present Government did not allow the pace of development to slow down due to lack of resources. As soon as we assumed power, we took tough decisions and started efforts to mobilize additional resources. Due to changes in State Excise Policy, an increase of Rs.359 crore is expected in State Excise Duty in 2023-24 as compared to the previous year. Last year, Rs.1,370 crores were received as VAT, which is estimated to be Rs.1,773 crores by the end of 2023-24. State Excise Duty and VAT together are expected to register a growth rate of 22 percent. It is estimated that approximately Rs.116 crore will be received through 'Milk Cess'. The resources thus raised will be used for the development and welfare of

the people of the State. Our Government will make every possible effort to make the State '**self-reliant**', even if the toughest decisions are required to be taken for this.

17. Speaker Sir, there will be a need for additional financial resources to take the State towards **'self-reliance'**. Our Government has sent a proposal of Rs.9,906 crores to the Central Government as a relief for the loss caused by the recent disaster on the basis of **'Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)'**. Apart from this, about Rs.8,000 crores are lying with the Government of India on account of the contribution made by the employees who have shifted from NPS to OPS. The State Government is yet to receive about Rs.4,500 crore from the share in the projects of Bhakra-Beas Management Board'. Overall, the State Government can get an additional amount of Rs.22,406 crores. I would request all the Hon'ble Members of this House, especially the Hon'ble Members of the opposition, to join hands to get this amount released from the Government of India at the earliest in order to take the State's economy on the trajectory of **'self-reliance'**.

National Economy

18. Speaker Sir, the Indian economy is estimated to grow at the rate of 7.3 percent during 2023-24. A growth rate of 5 percent or more is expected in all sectors. However, the growth rate in the agriculture sector is estimated at only 1.8 percent, which points towards serious structural problems in the agricultural sector.

State Economy

19. Speaker Sir, the growth rate of the State's economy is estimated to be 7.1 percent during 2023-24 as compared to 6.9 percent during 2022-23. During 2023-24, the per capita income in Himachal is estimated at Rs.2,35,199. The State's Gross Domestic Product is estimated to be Rs.2,07,430 crore in 2023-24.

Development Budget

20. Speaker Sir, it is proposed to spend Rs.9,990 crore for the State Development Budget during 2024-25. It is proposed to spend Rs.2,516 crore for 'Scheduled Caste Development Programme', Rs.899 crore for 'Tribal Development Programme' and Rs.110 crore for 'Backward Area Development Programme'. Apart from this, an outlay of Rs.5,280 crore is proposed for Central Schemes.

21. In order to convert the challenges in the development process of the State into opportunities, a **"Himachal Pradesh Transformation Cell (HPTC)"** will be established in the Planning Department. The HPTC will give suggestions to accelerate the development of the State based on best practices followed at local, national and international level. Along with this, a separate **"Sustainable Development Goals Coordination Centre"** will be established in the Planning Department for monitoring and evaluation of the development programmes. Both these units will start functioning from the next financial year.

Agriculture/value addition/Animal Husbandry and Cow Protection.

22. Speaker Sir, the agriculture sector is the backbone of the State's economy, which is directly or indirectly linked with about 69 percent of the State's population. Our Government has always been committed to increasing the income of the farmers of the State.

23. The State Government will promote self-employment in natural farming. I announce a new scheme **"Rajiv Gandhi Prakritik Kheti Start-up Yojana"** as the 3rd component of Rs.680 crore 'Rajiv Gandhi Start-up Yojana' aimed at increasing the income of farmers. Under this, in the first phase, 10 farmers from each Panchayat will be encouraged for **'Chemical Free Farming'** resulting in about 36,000 farmers adopting the natural farming. Farmers who are already doing farming will be given priority. As the farmers continue to join this scheme and use cow dung instead of urea and 12-32-16 fertilizer in the production of wheat and urea in maize, I announce that their grains will be purchased at a minimum support price (MSP). With the aim of motivating unemployed youth for natural farming, maximum of 20 quintals of naturally grown grains per family will be procured by the Government at the MSP of Rs.40 per kg and maize at the rate of Rs.30 per kg. The MSP given by our Government is the highest in the country. This is another effort of our Government for making Himachal Pradesh **'Self-Reliant'**. This will provide a security net to those farmers who practice natural farming and youth in rural areas will be motivated for self-employment in the agriculture sector. With this, 15,000 acres of land will be certified as natural farming land through Web Portal. 10 new 'Farmer Producer Organizations (FPOs)' will be formed under the intervention. Rs.50 crore will be spent on this during 2024-25. In addition to this, Rs.10 crore will be spent for giving assistance to the farmers for wire mesh and barbed wire.

24. Our Government will ensure equitable development of 2,500 agricultural clusters over a period of 3 to 5 years under 'Himachal Pradesh Agriculture Mission'. Under this Mission, High Value crops will be promoted in various areas based on climate, so that the income of farmers can increase by maximum amount in the shortest time.

25. The year 2023 was celebrated all over the world as 'International year of Millets'. A detailed action plan will be prepared to promote the production of coarse grains in the State, through which farmers and other people of the State will be sensitized about the cultural importance and nutritional value of coarse grains.

26. Under the 'JICA Phase-II project', 50,000 hectares of additional land will be brought under vegetable cultivation in 2024-25. Apart from this, provision will be made for the value addition to the produce of beneficiary farmers through food processing and necessary marketing linkages will be developed to sell these products.

27. Speake Sir, I announce the construction and upgradation of the following mandis in 2024-25:-

- ✓ New mandis will be constructed at Mehndali and Shilaru in Shimla district and Bandrol in Kullu district.
- ✓ Paonta Sahib, Khairi, Ghanduri and Nauhradhar in Sirmaur; Chauribihal, Patlikuhal and Khegsu in Kullu; Takoli and Kangni in Mandi; Jasur, Passu and Palampur in Kangra; and, Parwanoo, Kunihar and Waknaghat mandis in Solan will be upgraded.

28. To bring transparency in all the transactions taking place in the mandis, all their processes as well as the functioning of the yards of the Agricultural Produce Market Committees and the State Agricultural Marketing Board will be digitized and brought to a common platform.

29. Chat Bot and AI based tools will be provided on the web enabled agriculture portal and mobile app will be launched enabling access to land records with the provision of helpdesk for convenience of the farmers. Technical support will be taken from the Department of Digital Technologies and Governance and 'Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC)' for this.

30. With the aim of increasing the income of farmers through vegetable production, the farmers of the State will be given saplings of good quality and necessary training will also be provided to them. For this, a **'Centre of Excellence for Vegetable Nursery Production'** will be established which will be able to provide 8 to 10 lakh saplings in a year.

31. The government farms of the entire State will be revived and upgraded for the multiplication of high yield seeds in a phased manner. In 2024, Bhattu Farm in Kangra, Berti Farm in Solan and Bhangani Farm in Sirmaur will be upgraded and through these, latest agricultural technology, nursery production etc. will be showcased.

32. My Government will ensure increase in the income of farmers by linking animal husbandry and milk production with natural farming. With the aim of encouraging farmers to increase milk production and reduce use of chemical fertilizers, I announce to procure the cow and buffalo milk by the Government by increasing the minimum support price from the current Rs.38 per litre to Rs.45 per litre; and, from Rs.47 to Rs.55 per litre, respectively with effect from 1st April, 2024. This is the first time in the history of Himachal that minimum support price has been ensured even on milk. Himachal Pradesh is the only State in the entire India to buy milk at the minimum support price. This increased amount will be given to milk producers according to the quality of milk. If a farmer gets a higher price in the open market, she/he will be free to sell it in the open market. More dung will be available due to increased livestock, which will help in natural farming. The wheat produced through natural farming will be certified and procured by the Government. We are working towards the goal of enabling farmer families to earn a fixed income by encouraging milk production and linking it to natural farming in a phased manner so that we can fulfil the promises made before the elections. An additional expenditure of about Rs.150 crore will be incurred on it in 2024-25, which will help in supporting this intervention.

33. It takes a lot of time to process the reimbursement claims against the market fees paid by milk producing societies like Himachal Pradesh Milk Federation (MILKFED), Kamdhenu Hitkari Manch etc. by the Agricultural Produce Market Committee (APMC).

Due to this, a lot of money of these societies remains with the Committee for a long time. I announce that from 1st April, 2024, the fees charged by APMC from milk producing societies will be waived-off. This will benefit these societies a lot.

34. My aim is that the farmers and animal rearers should not only get the cost-based price of milk produced but also get quality bonus. To achieve this goal, my Government is working keeping a definite time line in mind. This will be achieved with the joint efforts of the Government and farmers. Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam will start a skilling programme for providing necessary skills in the field of Animal Husbandry to youth of the State.

36. I announce the establishment of 1.5 LLPD (Lakh Litre Per Day) capacity **'Fully Automated Milk and Milk Products Plant'** at Dhagwar in Kangra during the year 2024-25 under the 'Him-Ganga' scheme. Land has been made available for this plant and its capacity will later be increased to 3 LLPD. In this plant, milk powder will be produced with State-of-the-art technology so that the milk in excess of market demand is preserved for a longer duration. In addition, curd, khoya, ghee, ice cream, flavoured milk, processed cheese and other products will also be produced. Along with this, packaging facility with UHT (Ultra Heat Technology) will also be made available here.

36. An additional plant with a capacity of 50,000 LPD will be made functional in Duttnagar. Priority will also be given to the maintenance and upgradation of milk plants currently working in different districts.

37. 'Milk Processing Plants' with modern technology will be established in Una and Hamirpur also on which approximately Rs.50 crore will be spent.

38. 200 refrigerated milk vans will be provided to the local youth at a subsidy of 50 percent for transporting the milk from farmers/collection centres to the milk processing plants.

39. With the aim of providing good breed animals to the farmers, I announce the establishment of **'Artificial Insemination Training Centre'** at Darlaghat in Solan district. This facility will be used for training of farmers for artificial insemination.

40. 44 mobile veterinary vans have already been purchased to provide medical facilities for serious animal diseases through specialist veterinarians. This service will be fully started in the year 2024. A veterinarian and a pharmacist will be deployed in each van. Animal rearers will be able to get treatment facilities for their cattle and other information related to animal husbandry can be accessed by calling toll free phone number 1962 from anywhere in the State.

41. Under 'Rashtriya Gokul Mission', a **'Centre of Excellence'** will be established at Basal in Una district at a cost of Rs.44 crore with technical assistance from Denmark. The land required for this centre has been transferred in the name of Animal Husbandry Department.

42. In changing times, there is also a need for reorganizing and restructuring of the Animal Husbandry Department. A detailed plan will be made for

rationalization of departmental schemes and restructuring the department, for which, an expert committee will be formed. A detailed action plan to increase the milk productivity in the State will be prepared and implemented under the 'National Dairy Plan-II' through MILKFED.

43. Himachal Pradesh is also a State of sheep and goat rearers. There are 8 lakh sheep and 11 lakh goats in the State. There is no separate provision for FMD Vaccine, deworming medicine and other medicines for sheep and goats. No provision has been made for this even by the Government of India. Other major problems of sheep-goat farmers include improvement in Dipping and drenching processes, improvement in the system of wool harvesting, depletion of traditional pastures and paths, sharp fall in the prices of wool due to changes in the international trade. I announce the launch of a new scheme **"Bhed Bakri Paalak Protsahan Yojana"** to address above issues. An additional amount of Rs.10 crore will be spent on this scheme.

44. A State Level Task Force will be formed to solve the problem of increasing number of stray animals in the State which will suggest guidelines for transferring these animals in nearby Cow-Sanctuaries and Gau-Sadans in consultation with the farmers and local communities within 3 months. This Task Force will give suggestions to construct new and maintain and operate the existing Cow-Sanctuaries and Gau-Sadans.

45. I am happy to announce the increase the financial assistance of Rs.700 to Rs.1,200 per cow per month for dependent cows in the private Gaushalas.

Rs.582 crore are proposed for Agriculture sector.

46. Speaker Sir, the horticulturalists of the State have made a major contribution to the economy of Himachal Pradesh. Increasing the income of horticulturalists has always been one of the priorities of our Government. I announce to complete the following development works in the horticulture sector during 2024-25 at a cost of Rs.300 crore:- **Horticulture**

- Construction of 75 minor irrigation schemes.
- Plantation of high density sub-tropical fruit trees will be done in about 1,200 hectare area which will benefit about 6,500 farmer families of 80 farmer clusters.
- A **'Centre of Excellence in Horticulture'** will be established at a cost of Rs.12 crore which will act as 'One Stop Resource Centre' for all the needs related to quality, skill, tourism and marketing related to horticulture.
- 2 State-of-the-art Fruit Processing Units will be established in sub-tropical areas of the State.
- A '**Foundation Block'** for mother trees/bud wood banks will be set up for the promotion of guava, lemon and other sub-tropical fruits and their development at a cost of Rs.5 crore.

47. I, after having consultations with the orchardists, announce that the use of universal carton will be started from the apple season for 2024. A committee has been constituted in December 2023 under the chairmanship of Secretary, Agriculture, to suggest guidelines in this direction.

48. Necessary guidelines will be prepared in collaboration with Dr. Y.S. Parmar Horticulture and Forestry University to promote the production of high return fruits like dragon fruit, avocado, blue berry, macadamia nut etc. in the State. This will lead to a rapid and certain increase in the income of the farmers of the State.

49. Speaker Sir, in view of the increasing number of tourists in the State, there is a need to promote **'Horticulture Tourism'**. A policy will be made in collaboration with the Rural Development Department, Horticulture Department and Tourism Department to develop big orchards and groups of orchards located in the State from the point of view of rural tourism. Under this policy, necessary training and other assistance will be provided to interested horticulturalists.

Rs. 531 crore are proposed for Horticulture sector.

Fisheries

50. Speaker Sir, with the aim of increasing the income of about 13,000 fishermen of the State, I make the following announcements:—

- ✓ Fishermen will be given financial assistance for construction of new fishing ponds in an area of 20 hectares at a subsidy of 80 percent.

- ✓ A new 'Centre of Excellence' having a 'Carp Fish Farm' will be established in Hamirpur District.
- ✓ 'Brood Bank' will be set up at Nalagarh-based 'Fish Seed Farm' at a cost of Rs.5 crore.
- ✓ Motorcycles, three-wheelers and Ice-boxes will be made available to the fishermen of the State at subsidized rates.
- ✓ 10 new large 'Biofloc Fish Production' ponds and 10 new small scale 'Biofloc Fish Production' units will be established.
- ✓ Three new 'Feed Mills' will be established.
- ✓ Two new ice plants will be set up.

51. Apart from this, 150 new trout fish production units and two new trout hatcheries will be established in the cold areas of the State to promote trout fish production in the private sector.

Energy/Multi-purpose projects.

52. Speaker Sir, heavy loss has been caused to infrastructure including Larji Power House due to recent incessant rains. The total loss to the Larji project has been estimated as Rs.658 crore. Unit No. 1 of the Larji Power House has been fully restored and the other two units will also be restored shortly.

53. The loan agreement has been signed with the World Bank for implementation of 'Himachal Pradesh Power Sector Development Programme' with a cost of approximately Rs.2,000 crore. The work for ensuring

24X7 power supply in 13 towns of the State with the help of Smart Grid Technology will be started under it soon.

54. With an aim to make Himachal Pradesh the first 'Green Energy' State of the country by 2026 and to promote solar energy in the State, I make the following announcements:—

- The foundation stone of Himachal's largest ‘Solar Power Project’ with 32 MW capacity located at Pekhubella was laid on 2nd December, 2023. I am happy to announce that it will be commissioned by the end of March, 2024.

- The ‘Aghlor Solar Power Project’ with an installed capacity of 10 MW in Una will be ready for commissioning by June, 2024.

- Bhanjal (Una) Solar Power Project with an installed capacity of 5 MW will be dedicated to the people of the State by September, 2024.

- The implementation of 'Rajiv Gandhi Start-up Yojana', envisaging the installation of solar panels ranging from 100 to 500 KW on the owned land at 45 percent subsidy will be given pace. The target of harnessing 100 MW of solar energy has been envisaged under the scheme in the first phase.

- Registration of solar energy projects to be established on private land will be kept open for the entire year so that exploitation of 100 MW solar capacity can be realized soon.

- Grid connected Solar Roof Top Plants and 'Solar Water Heating System' will be installed in the Baal-Baalika Aashrams, old age homes and 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding School' in the State.

- It will be made mandatory to supply at least 20 percent of the connected load in all Government buildings through grid connected 'Roof Top Solar Plants' in a phased manner.

- In Solan, Palampur and Dharamshala Municipal Corporations, it will be made mandatory to install 'Solar Water Heating System' in new buildings for all the domestic consumers to get the NOC. Installation of 'Roof Top Solar Plants' will be made mandatory on the roofs of all the Government buildings located in these Corporations in a phased manner.

- The work of setting up 5 solar parks with a capacity of 501 MW and other solar power projects with a capacity of 212 MW will be started in Una, Kangra, Solan, Sirmaur, Mandi and Shimla districts.

55. A detailed action plan will be implemented across the State under Re-vamped Distribution Sector Scheme (RDSS) to reduce Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses at a cost of approximately Rs.1,885 crore. This will increase the quality of power supply apart from ensuring financial sustainability of the distribution sector.

56. It is the need of the hour to have an Efficient Transmission and Distribution Network along with robust power generation base, so that not only the electricity demand of the people of the State is met but the surplus power can also be sold to other States when required. To further strengthen this, the work on 4 transmission lines at a cost of Rs.96 crore and 6 Extra High Voltage (EHV) sub-stations will be completed at a cost of Rs.290 crore during 2024-25.

57. The transmission assets of the State have been linked with the National Grid through 'Central Transmission Utility System'. The construction work of 'Joint Control Centre (JCC)' in Kunihar and sub-station in Dehan of Kangra will be completed in 2024-25. This will also facilitate quick maintenance of transmission lines.

Tourism

58. Speaker Sir, the announcement of making Kangra district the tourism capital of the State was made in the last budget. As a follow-up to it, notification under Section 11 for the expansion of Gaggal Airport in Kangra has been issued on 7th July, 2023. For this, the Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan will be finalized soon and the land acquisition work will be started. Apart from this, the DPR of Mandi Airport prepared by WAPCOS Ltd. is being examined.

59. Out of the total 16 proposed heliports in the State, 9 heliports viz. Jaskot in Hamirpur; Rakkar and Palampur in Kangra; Sultanpur in Chamba; Aaloo Ground, Manali in Kullu; Sharbo in Kinnaur; and, Jispa, Sissu and Rangrik in Lahaul-Spiti will be developed in the first phase. The feasibility study of these 9 heliports has been obtained and Obstacle Limitation Survey (OLS) of Rakkar, Sultanpur and Palampur; and architectural designs of Rakkar and Palampur have been received. The DPRs of Rakkar, Sultanpur and Palampur heliports will be ready soon. Construction work of Heliports will be started at Rakkar, Palampur, Reckong-Peo and Chamba at a cost of Rs.13 crore per Heliport. The 2nd phase will see construction of Heliports at Pangi and Holi in Chamba, Auhar in Bilaspur, Dharkiyari in Sirmaur, Chanshal Dhar in Shimla, Jankaur Harr in Una and Galanag in Solan. Necessary assistance will be taken from 'Pawan Hans Limited' through Government of India.

60. Moving towards commitment for tourism development, a master plan has been prepared for the development and management of Pong Dam under Swadesh Darshan-2. Along with this, the following 5 tourist destinations will be developed from tourism point of view:—

- Chandratal, Kaza and Tandi in Lahaul-Spiti.
- Rackchham and Nako – Chango – Khab in Kinnaur.

61. I am happy to announce that a Sky Walk Bridge will be constructed in the famous tourist place Haasan Valley near Kufri.

62. With the aim of providing better facilities to the tourists during their stay in the State, all the Home Stay Units located in the State will be brought under the ambit of the 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act', so that their operations are streamlined and quality of services improve.

Health & Family Welfare and Medical Education.

63. Speaker Sir, the increasing number of cancer patients in the State is a matter of concern. Necessary medical facilities will have to be arranged for prevention and treatment of cancer in the State. I announce to establish a **"State Cancer Institute"** in 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' with the latest State of the Art diagnostic and treatment facilities at a cost of Rs.100 crore. A study will be conducted with the help of Indian Council of Medical Research (ICMR) to find out the reasons for increasing incidence of cancer in the State.

64. Speaker Sir, to provide the facility of chemotherapy and Palliative Care to the patients suffering from cancer in the State, **"Cancer Day Care Centres"** will be established in the district hospitals and selected 'Adarsh Swasthya Kendras'. There will be a provision of beds for all the patients undergoing chemotherapy in these centres and chemotherapy medicines will be included in the essential medicine list of the State so that the patients do not have to spend much money for chemotherapy.

65. A Linear Accelerator (LINAC) machine will be set up at a cost of Rs.21 crore at Indira Gandhi Medical College, Shimla for advanced radiotherapy treatment of cancer patients.

66. Work on 69 'Adarsh Swasthya Kendras' announced in the last budget is in various stages of completion and most of these will be completed in 2024-25. Rs.1 crore per Centre will be made available for procuring machinery and equipment during this year.

67. Efforts will be made to give pace to all the works in progress in PGI Satellite Centre, Una Centre. Our Government has made efforts to arrange necessary environmental clearances which were lying pending for last many years. All the started works will be completed on priority.

68. 'Hospital Management Information Service (HMIS)' will be established in 53 health institutions of the State in the first phase. With this, patients will be able to get better treatment on the basis of their medical history. In this sequence, **'Aayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs'** of about 57 lakh persons of the State have been created. ABHA ID for the remaining eligible population of the State will be issued soon.

69. In view of the increasing cases of Scrub Typhus in the State, I announce the establishment of a **"State level Scrub Typhus Research Unit"** at a cost of Rs.1 crore.

70. To encourage breastfeeding in newborn babies, 'Lactation Management Centres' will be established in Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda and Kamla Nehru Hospital, Shimla. X-Ray facility will be provided through private practitioners in those areas where health institutions do not have it.

71. By the end of 2026, one 'Integrated Public Health Lab' with all test facilities will be established in each district.

72. Construction work will be started in new nursing colleges in Nahan, Chamba and Hamirpur as announced in the last budget. Along with this, the General Nursing and Midwifery (GNM) school in Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda will be upgraded to Nursing College.

73. A 'Guest Worker Screening Project' will be started for screening of migrant workers working in Baddi, Barotiwala, Nalagarh, Parwanoo, Paonta and Una industrial areas.

74. All the previous Governments have started many schemes for the welfare of the people of the State. Two such schemes, 'HIMCARE' and 'SAHARA' were started in 2019 and their benefits have also reached the eligible persons. But after the empirical analysis of information, some structural and operational problems in their implementation have come to light in the absence of convergence and application of technology. This has resulted in duplication of efforts. I announce to remove these shortcomings and make some necessary reforms with the help of national level domain experts, so that the people in need can get timely benefits of these schemes. The implementation of both these schemes will continue as usual till such time.

Rs.3,415 crore are proposed for Health sector.

Quality Education.

75. Speaker Sir, the first Prime Minister of India, Pandit Jawahar Lal Nehru believed that today's children will make the India of tomorrow. The way we nurture them will decide the future of the country. This statement has become even more relevant in today's time because of the pace at which the changes are taking place due to technological advancements in the whole world and their impact on every sphere of life. In this rapidly changing new world, the education system will play a very important role in preparing children for an uncertain future.

76. It is necessary that our education system be inclusive, equitable, future-oriented, aware of new technology and sensitive to Indian values of life. We must create a conducive environment for assimilation of constitutional values from primary level to university level. In the Constitution of India, we the people of India have set for ourselves the objective of a sovereign, socialist, secular and a democratic republic. The objective of our education system is to prepare children for unity in diversity and building a multi-cultural India in accordance with this pious spirit.

77. My Government wishes that the children of Himachal Pradesh develop a healthy outlook towards life in accordance with the basic spirit of the Constitution and become the best in every skill, from basic literacy and numeracy to the use of Artificial Intelligence. To achieve this goal, we have initiated comprehensive reforms in the field of education.

78. Shared use of resources available in primary, elementary and higher education institutions is the

need of the hour. Cluster system has been started in the State with this objective and it is yielding positive results. It will be further expanded and strengthened. These institutions will be provided with quality class-rooms with appropriate size, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, learning software, proper seating facilities; full strength of teachers, playground, clean toilets along with other facilities.

79. In today's global era, it is an imperative that even the children of rural areas are connected with the world from home using latest technology and they get employment and self-employment anywhere in the world on the basis of their ability and skills in the coming time. Hence we have introduced the option of choosing English medium starting from the first standard. Research and various studies clearly show that the best time to learn a language is till the age of 12 years. Thus, the option of choosing English medium from the first class itself has its relevance. This decision will benefit all the children of the State and especially the village children.

80. According to the 'National Education Policy', 5+3+3+4 education system will be implemented at the school level in the State, which will also include a three year pre-school 'Baal Vaatika' curriculum. At present pre-schools are being run in more than 6,000 primary schools in the State. To strengthen this system, 6,000 Nursery Teachers will be appointed in the next financial year. Eligible Anganwadi Workers will also be given the opportunity to be selected as Nursery Teachers and for this they will also be made to undergo a 'Bridge Course'.

To implement this system smoothly in accordance with the 'National Education Policy', the minimum age for admission in the first class has been fixed at 6 years and for admission in the three classes of pre-primary, the minimum age limit has been fixed 3, 4 and 5 years, respectively.

81. Educational institutions in the entire State will be developed as 'Institution of Excellence (IOE)' in a phased manner by following the pre-determined parameters. In the year 2024-25, a target has been set to make 850 educational institutions as 'IOE' which include 500 primary schools, 100 high schools, 200 senior secondary schools and 50 degree colleges. These institutions will have smart classrooms and other facilities and all the teachers in full strength in place. Their performance will be evaluated periodically based on objective criteria. School/College Leadership training will be started so that the Principals/Headmasters of all the schools and colleges of the State can provide necessary leadership in the field of education.

82. For better coordination between schools and society and to increase community participation, it has been decided to start **"Apna Vidyalaya-Mera Vidyalaya-Mera Samman"** scheme. In this, while on the one hand everyone from the Chief Minister to the block level officers will adopt one educational institution, on the other hand, the community will be connected with the schools. Arrangements will also be made to provide free education through eligible and interested persons.

83. In every Sub-Division, the Sub-Divisional Officers will have to compulsorily organize a review

meeting of all the primary schools once in a month by rotation. In this meeting, the performance of not only the students but also of the teachers will be appraised. Interaction will also be held with the parents in this meeting. Appropriate decisions regarding maintenance of the schools will also be taken in it. Necessary guidelines will be issued in this regard.

84. The system of annual ranking of all the educational institutions of the State and the system of giving 'Performance Based Grant' to them will be started. This entire system will be developed through an online portal, and it will also be shared with the general public and parents for which a website will be developed.

85. While carrying out comprehensive reforms in the education sector, special focus is on qualitative education. The decisions taken so far include increasing the total teaching days in a year, fixed timings for sports and cultural activities, gradually reducing the non-teaching duties of teachers, and reducing the formalities of records in Mid Day Meal scheme. Instructions have been issued to keep teachers away from construction work of buildings in schools. The practice of asking for the same information repeatedly is being discouraged. It has also been observed that one teacher of every school is busy carrying Daak almost regularly and used to remain absent from school. This system has also been completely banned. To develop a sense of respect for their institution among teachers and children, schools have also been given the right to choose the uniform of their choice for their children in consultation with the parents. In the coming year, necessary changes will be

brought by thoroughly examining the processes, structure and rules from primary level to university level for improvement in quality of education.

86. To develop the culture of reading and teaching, a massive public campaign in the name of **"Padho Himachal"** will be started in the State in the year 2024-25. Along with schools, rural and urban communities will also be involved in this campaign. Under this campaign, libraries will be created in 500 educational institutions of the State for general readers and especially youth and participation of common people will be ensured in the management and working of libraries of these educational institutions.

87. I announce the construction of a library and a reading room with modern facilities each at every district and sub-divisional headquarters and Gram Panchayats. This will be completed in a phased manner. In the first phase, 493 libraries will be constructed at the Panchayat level and books and other facilities will be provided on which Rs.88 crore will be spent.

88. Trained teachers have a major contribution in improving the level of education. Therefore, to make the training of teachers more result oriented, changes will be made in the rules of District Institute of Education Training (DIETs) and State Council of Educational Research (SCERT) and their functioning will be re-oriented to make them effective. Similarly, State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) will be reorganized and made functional.

89. In those places where separate schools or colleges are running for girls and boys, a single co-educational institution will be started by merging them in consultation with the local residents. This will not only help in the academic development of children, but they will also emerge strong mentally with an improved personality. The State Government will bear the cost of transportation in picking and dropping the children to a nearby school in such areas where there is no primary schools within the radius of 3 to 5 Kilometres.

90. According to an estimate, India has to suffer a loss of Rs.49 arab 78 crore every year due to water-borne diseases. Two-thirds of India's districts are suffering from water shortage. A statewide campaign will be run to ensure that children get clean water to drink. I announce that children of Government schools, whose number is more than 8,50,000, will be provided with a safe and clean water bottle.

91. The curriculum being taught in the State will be re-evaluated in the context of Constitutional values and the rich cultural heritage of the State will be given representation in it. For this, courses on the history and culture of Himachal, Indian Constitution, health, and other subjects of general knowledge will be started compulsorily from class five. One period for sports and physical exercise will compulsorily be included in the timetable of schools. Priority will be given to the appointment of Physical Education Teachers as per requirement.

92. Self-help groups, in schools, with more than 500 children, will be encouraged to participate in preparing and serving food under Mid Day Meals.

93. Accreditation of colleges through National Assessment and Accreditation Council is a good medium to assess the efforts made in providing quality education in colleges of the State. In 2024-25, all the eligible colleges of the State will submit their claim for accreditation.

94. For the year 2024-25, the State Government has sent a proposal of Rs.1,052 crore for funding to the Government of India under the Samagra Shiksha Abhiyan and Rs.400 crore under the STARS Project. Apart from this, a proposal of Rs.1,000 crore under PM USHA and a proposal for a grant of Rs.477 crore under PM SHRI is also under consideration of the Government of India. I expect the Government of India to soon approve these proposals.

95. The previous Government has started building 'Atal Adarsh Vidyalayas' at three places in the State. My Government will not only provide the necessary funds to complete these but will also make them functional. A special cadre of employees will be created for 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools' and 'Atal Adarsh Vidyalayas' and these will be developed as educational institutions of international standards. In the first phase, I announce to start the construction work of five Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools, namely Lahdoo and Nagrota Bagwan (Kangra), Amlehar and Bhoranj (Hamirpur), and Sanghnai (Una).

Rs. 9,560 crore are proposed for Education sector.

Technical Education and Skill Development.

96. Speaker Sir, to prepare the youth of the State for employment and self-employment opportunities, it is necessary to provide skills as per the market demand. I make the following announcements in this respect:—

- B.Tech and Diploma courses in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) will be started in Rajiv Gandhi Government Engineering College, Nagrota Bagwan.

- Diploma course in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) will be started in Government Polytechnic, Sundernagar.

- Diploma course Computer Engineering and IOT will be started in Government Polytechnic, Hamirpur and Talwar.

- Atal Bihari Vajpayee Government Engineering College, Pragati Nagar will start B.Tech and Diploma courses in Civil Engineering .

- Classes will be started in Government Polytechnic, Jandaur from the academic session 2024-25.

97. 448 employers have been added to the EEMIS portal of the Labour and Employment Department so far. More private sector employers will be added to it and through this, 180 campus interviews will be organized in 2024-25. Keeping in view the interests of the workers in the unorganized sector, a target has

been set to register 20,87,000 workers in this sector by the end of 2024. Apart from this, the employment registration portal of the Labour and Employment Department will also be linked with the Common Service Centres (CSCs) so that the youth of the State can get themselves registered through these centres also.

Rs.330 crore are proposed for Technical Education sector.

Social Security Pension.

98. Speaker Sir, at present approximately Rs.1,260 crore is being spent for giving social security pension to the old age, widows, single women, disabled, leprosy patients with 7,84,000 beneficiaries getting its benefit. In 2024-25, 40,000 new eligible beneficiaries will be included in this scheme on which an additional expenditure of Rs.70 crore will be made.

Women and child development and welfare of weaker sections.

99. Speaker Sir, till now no educational institute is available in the State for higher education of disabled persons. I announce the establishment of a **'Centre of Excellence for Education of Divyangjans'** in Kandaghat for higher education of the disabled persons in the State. **'Institution for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)'** will also be shifted into this Centre. All the facilities including playground, residential accommodation and others will be provided for Divyang Children in the age group of 0-27 years in this Centre. Financial assistance for paying the rent of hired accommodation will be given to such eligible Divyang children who do not have any accommodation to live in.

100. With the aim of drawing the youth of the State away from drugs and taking them towards nation

building, a State level **"Model Drug Prevention and Rehabilitation Centre"** will be established in Kandaghat with all the facilities along with library, gym, indoor and outdoor sports etc. in this centre. It will also be ensured that this Centre is well connected with road and there is a Community Health Centre or a Civil Hospital in the vicinity of this centre which will have counselling facilities alongwith other medical facilities. A Statewide campaign will be started to sensitize and educate the youth and other stakeholders about ill effects of drug use and related issues. An 'effective monitoring and reporting system' starting from sub-division level right up to State level with clear cut responsibilities will also be established.

101. Speaker Sir, there has been a remarkable expansion of health services in Himachal Pradesh and our Government has always been making efforts to provide timely and quality health services to all sections of the State. I announce the launch of a new scheme **"Mukhyamantri Sukh Arogya Yojana"**. Under this, free medical facilities will be provided to all such farmers and elderly people above 70 years of age in the State who are not paying income tax or do not get any pension.

102. I also announce the launch of a new scheme **"Mukhya Mantri Sukh-Shiksha Yojana"**. Under this, the State Government will bear the expenses of the education of children up to 27 years of age of all such widows in the State, whose annual income from all sources is less than Rs.1 lakh. This assistance will be provided to these children after they get admission in

medical college, engineering college, NIT, IIM, IIT, Nursing, graduation/ postgraduation courses. Apart from this, Rs.1,000 per month will be deposited in the RD accounts of all eligible children of widows, destitute, divorced and disabled parents till they attain the age of 18 years. The annual premium for health insurance of all eligible women will be borne by the State Government. Approximately Rs.41 crore additional expenditure will be made on this.

103. Our Government is determined to ensure that the benefits of various schemes being run for social security reach the beneficiaries in time. I also announce that in case the meeting of 'District Development Committee' is not held on time, the Deputy Commissioner of the concerned district will be given the powers to approve the benefits to be given to various beneficiaries under welfare schemes. In such a situation, the approvals given will have to be mandatorily approved in the upcoming meeting of the District Welfare Committee.

104. GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, AutoCAD etc. will be included in the Post Graduate Diploma and other Diploma courses being run for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC and other beneficiaries so that they acquire skills as per the market demand and get employment accordingly.

Rs. 2,457 crore are proposed for Women and Child Development and Welfare of Weaker Sections.

Food Security

105. Speaker Sir, due to the disaster caused by excessive rains, our Government made available ration, LPG connections and cylinders immediately at no cost to the families affected by the disaster. This small assistance provided by our Government became a big support for the affected families in this time of crisis.

106. Mustard oil and refined oil being given through ration depots is fortified with vitamin 'A' and 'D' as per the norms of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Till now, this oil is available to the consumers only in a limited quantity from the ration depots. The consumers have to buy this oil from the open market at higher prices in the event of weddings, festivals and other functions. I announce that all consumers will be able to get this oil as per their requirement from ration depots starting from 1st April, 2024. This will provide benefit of approximately Rs.100 crore to women of the State.

107. To further strengthen the Public Distribution System, the Integrated Management of Public Distribution System (IMPDS) will be upgraded and National Portability will further be strengthened under One Nation – One Ration Card (ONORC). This will help in bringing transparency in providing articles as per the provisions of National Food Security Act (NFSA). Under this, a provision of Web based KYC will be made so that the beneficiaries can get the benefits of this scheme in any State. Warehouse-wise monitoring of flour allocated from flour mills will also be ensured.

More than Rs. 200 crore will be spent for food subsidy.

108. Speaker Sir, the 'Plastic Waste Management Units (PWMUs)' as announced last year and being constructed in each block, will be operationalized in 2024-25. Backward and forward linkages will be ensured in their operation so that other areas and communities can also benefit from them.

109. After achieving the target of having a model Panchayat in all the districts, this model will be replicated through convergence in other Panchayats in a phased manner.

110. With the aim of making the rural areas of the State clean, a target has been set to declare 5,000 additional villages as ODF+ (Open Defecation Free Plus) in 2024-25. Apart from this, depending on the availability of land, Faecal Sludge Management Plants will be established at least at 4 sites.

111. A target has been set to form 1,000 Self Help Groups in rural areas in 2024-25. Apart from giving an amount of about Rs.32 crore to these groups in the form of Revolving Fund and Community Investment Fund, a target has also been set to give them a loan of about Rs.50 crore. About Rs.100 crore will be spent on Self Help Groups.

112. The accounts of all the Panchayats have been linked to the e-Gram Swaraj Software application. This system will be further strengthened for the optimal allocation of resources and monitoring expenditure of all Panchayats.

113. In 2024-25, Rs.352 crore will be spent on Panchayati Raj Institutions as per the recommendations

of the Fifteenth Finance Commission and Rs.448 crore will be spent on the recommendations of the Sixth State Finance Commission.

114. The then UPA Government introduced 'Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)' which has proved to be a boon for the rural unemployed. Through this, MGNREGA workers are not only getting employment but are also contributing in the creation of public assets in rural areas. I announce to increase the daily wage of MGNREGA workers from the current Rs.240 to Rs.300. This unprecedented increase in the wages has been the first in the history of Himachal Pradesh. This will give pace to growth of rural economy of the State in achieving **"Self-reliance".** With this, the State Government will pay a top-up of Rs.76 per day to MGNREGA workers out of its own resources. In addition to this, such "**Widow, Single/Destitute/ Divyang Women MGNREGA Workers"** whose annual income is less than Rs.2.5 lakh and have completed 100 days of wages in a year will be given assistance up to Rs.3 lakh for constructing a house, provided that this assistance has not been availed under any other program by them.

115. I am happy to announce increase in the honorarium of representatives of the Panchayati Raj Institutions as under:—

- With an increase of Rs.4,000 per month, Chairman, Zila Parishad will get Rs.24,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.3,000 per month, Vice Chairman, Zila Parishad will get Rs.18,000 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,300 per month, Member, Zila Parishad will get Rs.7,800 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,900 per month, Chairman, Panchayat Samiti will get Rs.11,400 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,400 per month, Vice Chairman, Panchayat Samiti will get Rs.8,400 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,200 per month, Member, Panchayat Samiti will get Rs.7,200 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,200 per month, Pradhan, Gram Panchayat will get Rs.7,200 per month honorarium.

- With an increase of Rs.800 per month, Up-Pradhan, Gram Panchayat will get Rs.4,800 per month honorarium.

- Member, Gram Panchayat will now get Rs.750 per sitting of the Gram Panchayat with an increase of Rs.250 per sitting.

Rs. 2,356 crore are proposed for Panchayati Raj and Rural Development sector.

National Economy.

116. Speaker Sir, approval of plans for construction of houses will be given on a single portal through AUTODCR starting from 2024-25. If any deficiency is found after uploading the house map and other

documents on this portal, then the applicant will be able to submit additional information by viewing it online. Through this portal, private professionals will also be authorized to give permissions for residential plots up to 500 square meters.

117. I am happy to announce an increase in the honorarium of Urban Local Bodies representatives as per following:—

- With an increase of Rs.4,000 per month, Mayor, Municipal Corporation will get Rs.24,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.3,000 per month, Deputy Mayor, Municipal Corporation will get Rs.18,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.1,400 per month, Councillor, Municipal Corporation will get Rs.8,400 per month honorarium.
- With an increase of Rs.1,700 per month, President, Nagar Parishad will get Rs.10,200 per month honorarium.
- With an increase of Rs.1,400 per month, Vice President, Nagar Parishad will get Rs.8,400 per month honorarium.
- With an increase of Rs.700 per month, Councillor, Nagar Parishad will get Rs.4,200 per month honorarium.
- With an increase of Rs.1,400 per month, Pradhan, Nagar Panchayat will get Rs.8,400 per month honorarium.

- With an increase of Rs.1,100 per month, Up-Pradhan, Nagar Panchayat will get Rs.6,600 per month honorarium.

- With an increase of Rs.700 per month, Member, Nagar Panchayat will get Rs.4,200 per month honorarium.

118. An Environment Cell will be set up in the Directorate of Urban Development at the State level to streamline and monitor waste management in urban areas.

119. To improve the functioning of urban bodies and for the convenience of the general public, the functioning of urban bodies will be digitalized. For this, a 'State Project Monitoring Unit' will be established, which will prove helpful in improving the functioning of urban bodies with the help of domain experts by online planning, monitoring, implementation and reporting. Under this initiative, various fees and taxes can be collected online in urban areas and various permits and NOCs can be issued online. Under this, the accounts of urban bodies will be digitized. With the help of AGiSAC, asset valuation will be done in all urban bodies.

120. Speaker Sir, I announce to launch a new scheme **"Maharishi Valmiki Kamgar Awas Yojana"** to help the brothers of the Valmiki community for construction of houses. Under this, such sanitation workers of Valmiki community, whose annual income is less than Rs.2.5 lakh and do not have their own house, will be given assistance of Rs.3 lakh to build a house.

Housing

121. I announce to increase the assistance from Rs.1.5 lakh being given for constructing a house to the beneficiaries under the 'Mukhya Mantri Widhwa Evam Ekal Naari Aawas Yojana' to Rs.3 lakh. This assistance will be available to such beneficiaries whose annual income is less than Rs.2.5 lakh.

122. Houses will be allocated to such persons belonging to Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers in Municipal Corporations Dharamshala, Solan and Shimla; and Municipal Councils Nalagarh and Parwanoo whose annual income is less than Rs.3 lakh. Preference will be given to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC classes, widows, destitute women, divyangs who fulfil the eligibility criteria.

Jal Shakti

123. Speaker Sir, drinking water facility is being provided in the rural areas of the State under Jal-Jeevan Mission and 2 projects funded by New Development Bank (BRICS-NDB) and Asian Development Bank (ADB), respectively. It is targeted to complete 4 antifreeze drinking water projects in Kinnaur, Chamba and Lahaul & Spiti in 2024-25 at a cost of Rs.29 crore. 24 drinking water supply schemes funded by NDB, and 186 drinking water schemes funded by ADB, are at various stages of implementation and will be completed within the stipulated time. Through these two projects, 20,663 families will be benefited from Partially Covered (PC) Schemes and 79,282 families will be benefited with the Functional Household Tap Connections (FHTC).

124. With the aim of improving the drinking water supply in urban areas, I make the following announcements for 2024-25:—

- The work of drinking water supply schemes with the capacity of 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) will be completed in 4 cities namely Jawali, Hamirpur, Baijnath-Paprola and Ner Chowk, respectively.

- Similarly, the execution of drinking water schemes for Amb and Bhuntar at a cost of Rs.33 crore will be expedited and efforts will be made to complete them by the end of 2024-25.

- Work on drinking water improvement schemes for Nahan, Arki, Nirmand, Palampur and Joginder Nagar at a cost of Rs.112 crore will be started soon.

- In the direction of implementation of 24×7 drinking water supply schemes announced by me in my last budget, work on drinking water supply schemes has been started in Ward No. 6 and 7 of Rampur, Nalagarh and Chamba. And work will start on these schemes soon in other 9 cities.

125. The announcement made in my last budget in the direction of improving the quality of drinking water in Himachal Pradesh has been implemented and after forming the Village Water and Sanitation Committees with the participation of local women and they have been trained. So far, 69 testing labs have been

established, out of which 62 have been accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration. This system will be further strengthened in 2024-25 so that clean and germ-free drinking water is made available to the people of the State.

126. As per the announcement made in the last budget, 37 such areas have been identified for installation of UV system in those drinking water schemes and STPs where water sources are either polluted or have the potential to be so. Necessary steps will be taken to install UV system at the identified sites to provide pure drinking water.

127. The ongoing work on sewerage projects in Gagret, Dalhousie, Chuwari, Rewalsar, Bhota, Santokhgarh, Baijnath-Paprola and Ner Chowk will be accelerated, and efforts will be made to complete them in 2024-25. The construction work of sewerage projects in Rajgarh, Banjar, Chopal, Nerwa and Shahpur will be completed in 2024-25. Apart from the above, construction works of sewerage projects in 16 rural areas approved by NABARD will be awarded in 2024-25. Under the project approved by AFD at a cost of Rs.817 crore, Sewerage Treatment Plants (STP)/Waste Treatment Plants (WTP) have been approved for Manali, Palampur, Nahan, Karsog and Bilaspur along with a drinking water supply scheme for Manali. Of these, the work of Manali sewerage network is in progress and the remaining works will also be started soon.

128. Work on 14 Surface Minor Irrigation Schemes (SMISs) at a cost of Rs.380 crore is in various stages of

execution. About 9,700 hectares of CCA will be created through these schemes. These schemes are approved under 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' and will be given pace based on the funds released by the Government of India. Out of the 4 schemes approved under the 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana', an amount of about Rs.53 lakh will be made available under Tribal Development Programme to complete the scheme for Labrang Garden Colony and Pooh.

129. The Phina Singh Multipurpose Medium Irrigation Project at a cost of Rs.644 crore was approved in the meeting of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DOWR,RD&GR) held under the chairmanship of the Secretary. It has been recommended for funding under 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Accelerated Irrigation Benefit Programme (PMKSY-AIBP)'. This project will help in the creation of 4,025 hectares of CCA. Apart from this, 1.88 MW hydropower will be produced after its completion. About Rs.290 crore have already been spent by the State Government from its own resources on this project. The implementation of this project will be accelerated on the basis of funds released by the Centre.

Rs.3,365 crore are proposed for Jal Shakti Vibhag.

Roads and Bridges.

130. Speaker Sir, due to the disaster that occurred during excessive rains last year, there has been extensive damage to roads and bridges in the State. Our Government lost no time and started relief and restoration work and within a very short time all the

main roads were opened to the public. Within a short period, the damaged roads were restored with the help of 18 Bailley Bridges and 27 ropeways. Through this August House, I heartily thank all the elected public representatives and Government officers and employees who stood day and night with the people of the State and accomplished the restoration work.

131. In the absence of railways and water transport, the State needs a strong road network. During the last 53 years, many new roads have been constructed in the State and many villages are connected through them. At present there are 40,703 Kilometres of motorable roads, 34,055 Kilometres of metalled roads and 2,478 bridges in the State. Out of total 3,615 Gram Panchayats, 3,578 Gram Panchayats have been connected with motorable or jeepable roads. Of the remaining Panchayats, 10 more Panchayats will be connected by motorable roads during 2024-25.

132. Our Government has received approval of Rs.2,643 crore for 254 roads with the total length of 2,683 Kilometres under 'Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana-III'. Under this scheme, the following works will be completed in 2024-25:—

- ❖ Upgradation of 500 Kilometres of roads.
- ❖ Construction of 325 Kilometres of new roads.
- ❖ Construction of 8 bridges.
- ❖ 15 habitations will be connected by road.

- ❖ Thus, under 'Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana', 825 Kilometres long roads and 8 bridges will be constructed.
- ❖ Apart from this, cross drainage work on 150 Kilometres long roads will be done under 'Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana-I and II'.

133. Our Government has set a target to completing 19 works including 13 bridges on 115 Kilometres long National Highways with an expenditure of Rs.631 crore in 2024-25. Apart from this, a proposal will be sent to the Central Government for two-laning and four-laning of National Highways at a cost of Rs.4,490 crore. Among these, the major works on National Highways are as follows:—

- Sainj-Luhri-Aut at a cost of Rs.500 crore.
- Construction of Jalori Pass Tunnel on Sainj-Luhri-Aut National Highway at a cost of Rs.750 crore.
- Nagrota – Bagwan – Ranital at a cost of Rs.200 crore.
- Chamba-Bharmour at a cost of Rs.300 crore.
- Nahan-Kumharhatti at a cost of Rs.500 crore.
- Construction of bridges on various National Highways at a cost of approximately Rs.250 crore.
- Various other works at a cost of about Rs.2,000 crores.

134. During the coming year, 205 Kilometres long new roads, cross drainage work on 305 Kilometres long roads, 425 Kilometres long tarred roads and 27 bridges will be constructed under RIDF through NABARD.

135. The construction work of the following 5 approved roads under the Central Road Infrastructure Fund (CRIF) will be completed in 2024-25:—

- Repair work of damage caused by rain on Jiya-Manikaran road.
- Upgradation of Shahpur - Sihunta - Chuwari road.
- Construction of a bridge connecting Terrace and Sthana on river Beas.
- Upgradation of Baghchhal-Mehre-Barsar road.
- Construction of bridge on Swan River at Pandoga -Tiuri.

136. Speaker Sir, keeping in view environmental protection and cost reduction, waste plastic material will be used for undertaking maintenance work of 230 Kilometres long roads in 2024-25. Apart from this, Calcium Chloride and Brine Solution will be used on high altitude roads so that ice layer does not accumulate on the surface of these roads in winter and possible accidents are avoided.

137. The following roads and related construction works will be completed by our Government in 2024-25:—

- ✓ Construction of total 860 Kilometres long roads.

- ✓ Cross drainage work on 1,067 Kilometres long roads.
- ✓ Metalling and tarring on 1,075 Kilometres long roads.
- ✓ Construction of 57 bridges.
- ✓ Connecting 40 villages of 10 Panchayats by road.

Rs. 4,317 crore are proposed for roads and bridges.

Industry/ private Investment.

138. Speaker Sir, in view of the changing market conditions, it is very important to make changes in the "Industrial Investment Policy" notified in 2019 so that prospective investors can get all the approvals in the shortest possible time through a single instance. This will encourage investors to invest more. Our Government will bring a new **"Industrial Promotion and Investment Policy, 2024"** in view of the changing markets in 2024-25.

139. There are countless possibilities of self-employment in the industrial sector for the youth of the State. There is a need to encourage the youth in this direction. For this, I announce to bring a new **"Start-up Policy, 2024"** in 2024-25. Under this policy, provision will be made for special incentives for women for innovations. Start-ups initiated by women will be given maximum assistance of Rs.4 lakh for one year.

140. The Industries Sector contributes immensely to the development of the State. The endeavour of my Government is to provide best eco-system to this

sector. My Government had enhanced the Electricity Duty (ED) during last year's calamity to cover the resources required to undertake large scale restoration work. Now, when the situation has improved, I announce that the enhanced Electricity Duty will not be payable by those consumers who were granted relaxation in paying the ED till expiry of the admissible period as per the provisions of the 'Himachal Pradesh Industrial Policy, 2019'.

141. Speaker Sir, many steps have been taken effectively by our Government to curb illegal mining in the State. There is a need to make some changes in the mining policy of the State which is more than 10 years old. I announce that **"Himachal Pradesh Mines and Minerals Policy, 2024"** will be introduced in the State, the main objectives of which will be to stop illegal mining and increase the revenue of the State through scientific mining.

142. Separate standards will be set for fire services to deal with fire accidents due to various reasons in the industrial areas of the State. These norms will, depending on the number and type of industries in an industrial area, lay down SOPs for different measures to deal with fires caused by chemicals, electrical fires and fires caused by other reasons. The norms will also standardize the materials and equipment which include chemical protection suit, foam compound tank, dry chemical powder for dealing with fires caused by different reasons.

143. Baddi-Barotiwala-Nalagarh Industrial Area makes a great contribution in the resources and

employment generation of the State. Necessary infrastructure facilities in this area are necessary for both investors and workers alike. I announce the construction of a road from Sheetalpur to Jagatkhana in this area at a cost of Rs 70 crore. This road will connect 'Medical Device Park' Dherowal with Baddi Industrial Area.

144. Speaker Sir, in 2024-25, e-vehicle charging stations at 17 petrol pumps will be made operational. Apart from it, the 'State Electricity Board' and 'Indian Oil Corporation Ltd.' have been roped in for operationalizing e-vehicle charging stations at 33 more petrol pumps. In addition, 55 other e-vehicle charging stations in the Government sector will be made functional. **Transport**

145. After the announcement of phased replacement of diesel buses with electric buses in 2023-24, till now the fleet of electric buses has grown to 110 electric buses and 50 e-taxis. Taking this commitment forward, I announce that in 2024-25, 327 additional diesel buses will be replaced with electric buses. To ensure public participation in this initiative, in the initial phase, priorities have been sought from Hon'ble MLAs to run e-buses on 5 routes in each Legislative Assembly Constituency.

146. Under the 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana', 10,000 permits will be given to run e-taxis at 40 percent subsidy in 2024-25. Continuing with the efforts to make Himachal a 'Green State', I announce that in 2024-25, all the eligible vehicles of the Forest Department, HRTC, HPTDC and GAD will be replaced with e-vehicles.

147. Pratham Darshan service will be expanded to run buses to religious places. In the first phase, 6 buses have been started from different places for darshan of Shri Ayodhya Dham. In 2024-25, this bus service will also be run from other additional locations.

148. In the year 2024-25, under the 'Vehicle Scraping Policy'**, "Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** will be established in the State so that all the 12 districts of the State can avail this facility.

149. I announce that in 2024-25, all vehicles will be mandatorily required to pass the fitness test through Automated Testing Centres, so that there is no human error in declaring the vehicles fit for running.

150. e-challan and e-POS machines will be made available to the officers for online challan for the detected violations of transport rules.

151. Automated Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV Cameras) will be provided at all transport barriers so that tax evasion can be stopped and the Government can get additional resources. This system will also help the traffic to run smoothly.

152. The construction work of a 3.2 Kilometres long ropeway at a cost of Rs.272 crore will be started between Bijli Mahadev and Mohal in Kullu on Hybrid Annuity Model (HAM). The State Government will receive 50 percent of the profit from the operation of this ropeway.

153. The recent rains which occurred in the State caused heavy damages to Baglamukhi Ropeway, which

is being constructed at a cost of about Rs.54 crore. An amount of more than Rs.5 crore had to be spent for its stabilization. I am happy to announce that after completing the construction work of this ropeway, it will be dedicated to the people of the State this year itself.

154. Our Government will request the Government of India to lay broad gauge rail line from Kalka to Parwanoo for the convenience of the tourists and people of the State. Along with this, a request will also be made to the Government of India to lay the railway line from Jejon to Poliyan. With this, rail transport facility will be available to 'Bulk Drug Pharma Park' being constructed in the State. An expenditure of Rs.10 crore is expected in 2024-25 to conduct survey for these lines.

155. Speaker Sir, with the aim of promoting eco-tourism in the State, 93 Eco Tourism Sites will be outsourced for their operation and management in a phased manner. In the first phase, 13 Eco Tourism Sites have been finalized for outsourcing for which Request for Proposal (RFP) is being given final shape. All these sites will be outsourced in 2024-25. **Forest**

156. After the initiative taken by our Government, the permission for scientific silviculture felling of Khair trees has been granted by the Hon'ble Supreme Court as per working plans. This will not only increase the income of local people but will also motivate them to plant more trees after cutting existing Khair trees. A plan has been prepared to cut about 13,000 Khair trees in 10 Forest Divisions in 2024-25. This will also increase

the revenue of the State. Inspired by this decision of the Hon'ble Court, our Government will also file a petition for permission to cut Chil trees. This will not only generate additional revenue but will also improve the quality of the eco-system services.

157. Taking a step further in the pursuit of a 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks will be set-up in the peri-urban and urban areas. These parks shall be designed and developed using eco-friendly materials. The muck sites will also be restored through this intervention.

158. Speaker Sir, I announce to appoint one Van Mitra in all the 2,061 Forest Beats of the State to deal with all forest related matters at the Beat level. The process of their appointment will be completed in 2024-25. These Van Mitras will play an important role in the management of forests with the help of communities.

159. Along with this, I also announce to fill 100 vacant posts of Forest Guards in the Forest Department during 2024-25.

Rs. 834 crore are proposed for Forest Department.

Environment, Science and Technology.

160. Speaker Sir, for the Green and overall development and empowerment of the rural population of the State, I announce the launch of the **"Mukhya Mantri Harit Vikas Chhattravriti Yojana"**. Under this scheme, in the next 4 years, 2 villages will be selected in each Legislative Assembly Constituency and the Science Postgraduates and Engineering Graduates will be given scholarship for 2 years for research on climate change and environmental protection in those villages.

161. In view of the recent heavy rains and continuous changes in climate, the work of preparing Climate Change Action Plans at the district level will be started from 2024-25. Climate Change Action Plans will be implemented at the Panchayat level.

162. I announce that a Need Assessment Study (NAS) will be initiated in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the GIZ for mitigating the adverse effects of changing climate for sustainable development of agriculture and horticulture sectors.

163. To stop unscientific and illegal mining in the State, a GIS based App will be started with the help of which the mining activities taking place in the State will be closely monitored on real time basis.

164. A scheme will be started in the State to promote Geographical Indications (GI) through which the GI tagging of commercial products will be done so that the producers can get fair price for their products in the national and international markets.

Digitization, Governance and Information Technology.

165. Speaker Sir, I announce the following steps to be taken during 2024-25 in the direction of making the Governance more transparent and effective in the State:—

- ✓ A work plan will be made and rolled out enabling evidence based planning with the help of Artificial Intelligence (AI) and data analytics.
- ✓ An 'Online Sewa Portal' will be launched to deliver the already available online citizen

services to the people of the State more effectively and a mobile app will also be launched.

- ✓ After successful implementation of e-office in Himachal Pradesh Secretariat, Directorates, all DC and SP Offices and 253 field offices, the facility of e-signature as well as the facility of online dispatch will be provided in all the offices.

- ✓ To make the CM-Dashboard more effective, various departments will be linked with the Reporting Management Portal so that appropriate decisions are taken at appropriate time based on the latest information received from the departments.

- ✓ Artificial Intelligence will be used in the 'Mukhya Mantri Seva Sankalp' helpline so that the complaints received can be resolved in the shortest possible time.

- ✓ The DBT Portal developed last year will be linked with the National DBT Portal so that the information of both the Portals can be shared.

- ✓ For expeditious disposal of online applications for 5G connectivity made by investors, the Right of Way (RoW) Portal will be updated with necessary changes.

- ✓ The work of upgradation of the State Data Centre (SDC) will be completed by August, 2024 and latest technology will be used to

protect the data and other information available in it.

- ✓ After the successful implementation of Him Parivar Registry, various citizen services will be integrated with it so that the people of the State can get the benefits of various services in the shortest possible time.

Land Administration, Reforms Management

166. Speaker Sir, starting from 2024-25, under 'Megh-Jamabandi' the citizens will be able to get copies of land related records at any time. The facility of fee payment will also be made available on this portal through UPI/Debit Card/Credit Card etc.

167. Under 'Megh-Charge' module, provision will be made to complete all the processes online for taking loan through Kisan Credit Card. Through this, one will not have to make repeated visits to banks or financial institutions and tehsil offices. By completing all the formalities through this integrated module, the loan can be approved almost instantly.

168. Online payment of stamp duty, registration fee and other charges will be started through 'Megh-Panjikaran Module' to further simplify the property registration process. Similarly, the facility of online mutation will also be provided using 'Megh-Mutation Module'.

169. Description of many land records is available in difficult words. The work of getting these land records translated into various languages listed in Schedule VIII of the Constitution will be completed soon.

Resource mobilization.

170. Speaker Sir, in continuation of the measures to raise additional resources announced by me in the last budget, I make the following announcements:—

- ❖ For the convenience of taxpayers, a 'Mobile App' will be launched in 2024-25 for payment of VAT and other taxes. Using this feature, taxpayers will be able to make online tax payments.

- ❖ 'Kardaata Samvaad Abhiyaan' will be started with the aim of taking feedback from various taxpayers at important industrial and business Centres located in the State and getting information about the problems faced by them. This will help in making the taxation and excise system of the State simpler and more transparent.

Home/Law and Order.

171. Speaker Sir, Construction work will be carried out to provide residential facilities for the Police staff within the premises of Police Stations located in urban areas or in close vicinity of Police Stations at a cost of Rs.50 crore in 2024-25.

172. Speaker Sir, there has been no increase in the diet money of police personnel for a long time. I am happy to announce almost 5 times increase in the diet money to police personnel from the current level of Rs.210 to Rs.1,000. The Police Personnel will get a benefit of more than Rs.9,000 per annum. About 18,000 police personnel will benefit from this. This will entail an expenditure of more than Rs.16 crore per annum.

173. In the next 5 years, 1 percent of the population of the State will be brought under the 'Civil Defence Scheme'. This initiative will prove to be very helpful in disaster relief work in the eventuality of natural disaster.

174. To bring transparency in the process of issuing or withdrawing NOC 'Himachal Pradesh Fire Fighting Services Rules' will be notified.

175. I announce the opening of New sub-fire stations at Changar Baroh in Kangra; Kotli and Ladbhadol in Mandi and upgradation of fire post at Theog to fire sub station in 2024-25. Apart from this, I also announce the opening of fire units in Nirmand, Kunihar and Ubadesh (Kotkhai), Chhota Bhangal and Chuhar Valley of Kangra.

Youth Services and Sports.

176. With an aim of encouraging the youth of the State to actively participate in sports, a New Sports Policy (NSP) will be brought out in 2024-25. Under this, I am happy to announce the following:—

- The prize money for winning a gold medal in an individual event in the Olympic Games will be increased from Rs.3 crore to Rs.5 crore, for a silver medal from Rs.2 crore to Rs.3 crore and for a bronze medal from Rs.1 crore to Rs.2 crore.
- The prize money for winning gold medal in individual event in Asian Games will be increased from Rs.50 lakh to Rs.4 crore, for silver medal from Rs.30 lakh to Rs.2.5 crore and for bronze medal from Rs.20 lakh to Rs.1.5 crore.

- The prize money for winning gold medal in individual event in Commonwealth Games will be increased from Rs.50 lakh to Rs.3 crore, for silver medal from Rs.30 lakh to Rs.2 crore and for bronze medal from Rs.20 lakh to Rs.1 crore. Will be done.
- In case of Himachali players being part of the winning team in a team event, they will be given the above mentioned prize money in proportion of the representation.
- Players will be given AC 3 Tier fare to participate in sports events outside the State up to a distance of 200 kilometres, and for going to places more than 200 kilometres away, economy class air fare will be given.
- The number of sports included under 3 percent sports quota for various posts in in the Government departments will be increased from the present 43.
- After increasing the diet money given to players for various levels of sports events, I announce the following:—
    - All the players up to Elementary Education will be given Rs.250 per day for participating in games at any level held within the State.
    - All other players will be given Rs.400 per day for participating in the games at any level held within the State.
    - All the players will be given equal amount of Rs.500 per day for

participating in games held outside the State.

- All the players living in sports hostels of the State will be given diet money of Rs.250 and Rs.400 as above.

177. Speaker Sir, I announce to start the construction work of the following sports complexes in 2024-25:—

- Construction of an indoor stadium with modern facilities in Hamirpur.
- Construction of an indoor stadium in Panjoa, Una.
- Construction of an Indoor Sports Stadium for Manali in Bandrol.
- Construction of Indoor Stadium with swimming pool facility in Rehan.
- Construction of Indoor Stadium with swimming pool in Dehra.
- Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Kharidi, Nadaun.
- Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Kasumpati.
- Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Jaisinghpur.
- Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Dhalli Bypass.

Information and Public Relation.

178. Speaker Sir, with the objective of making Himachal Pradesh one of the favourite destinations for film shooting and other related activities, 'Himachal Pradesh Film Policy, 2024' will be implemented from 2024-25. Under this, a 'Film Development Council' will

be formed at the State level and a ‘Film Facilitation Cell’ will be established in the Information and Public Relations Department. A dedicated web portal will be set up to submit online applications and grant permissions for shooting of films.

179. To effectively disseminate and publicize Government schemes and development policies through various digital platforms, various web channels, news websites and social media influencers, ‘Digital Media Policy, 2024’ will be implemented.

180. Information related to Government programs and activities will be compiled through 'Himsoochana Kosh', so that the information required for publication and press can be retrieved from a single platform and press notes or articles can be printed.

Sanik welfare

181. Speaker Sir, Our Government will always be indebted to about 3,00,000 ex-servicemen, serving soldiers, war widows and gallantry award winners of the State for their services and sacrifices during times of war and peace.

182. I announce that the amount of financial assistance given to ex-servicemen above the age of 60 years who do not get any other pension will be increased from Rs.3,000 to Rs.5,000 per month.

183. Our Government will ensure that 15 percent of the posts reserved for ex-servicemen in various departments are filled-up on priority in 2024-25.

Cooperation

184. Speaker Sir, in continuation of the announcement made in my last budget for

computerization of Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS), the work of linking them with Cooperative Banks, Cooperative Department and National Database is in progress and it will be completed within the stipulated time limit of 2027. Moving forward in this direction, online registration of all cooperative societies is already being done.

185. The para-workers play an important role in implementation of different schemes in the State. I announce an increase in the honourarium of these para-workers as follows:—

Increase in Honorarium.

- With an increase of Rs.500 per month, Anganwari Workers will get Rs.10,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.400 per month, Mini Anganwari Workers will get Rs.7,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.300 per month, Anganwari Sahayikas will get Rs.5,500 per month honorarium.
- With an increase of Rs.300 per month, Asha Workers will get Rs.5,500 per month honorarium.
- Honorarium of Silai Teachers will increase by Rs.500 per month.
- With an increase of Rs.500 per month, Mid-Day Meal Workers will get Rs.4,500 per month honorarium.
- With an increase of Rs.600 per month, Jal Rakshak (Education Department) will get Rs.5,000 per month honorarium.

- With an increase of Rs.300 per month, Water Guards will get Rs.5,300 per month honorarium.
- With the increase of Rs.600 per month, the recently appointed Multi-Purpose Workers of Jal Shakti Vibhag will get Rs.5,000 per month.
- With an increase of Rs.300 per month, Para Fitters and Pump Operators will get Rs.6,300 per month honorarium.
- With an increase of Rs.1,000 per month, Panchayat Chowkidar will get Rs.8,000 per month honorarium.
- With an increase of Rs.300 per month, Revenue Chowkidars will get Rs.5,800 per month honorarium.
- With an increase of Rs.500 per month, Revenue Lambardaar will get Rs.4,200 per month honorarium.
- Rs.1,900 per month will be increased in the honorarium of SMC teachers.
- The IT teachers will get an increase of Rs.1,900 per month.
- Special Police Officer (SPOs) will get an increase of Rs.500 per month.

MLA Priorities

186. Speaker Sir, like every year, I make the following announcements on the basis of the suggestions that came forward during my meeting with the Hon'ble MLAs:—

- ✓ The MLA priority schemes of Shimla Legislative Assembly Constituency are not eligible for approval of NABARD under its

RIDF as it is an urban area. The same problem is also going to arise in the Legislative Assembly Constituencies falling in Dharamshala, Mandi, Solan and Palampur Municipal Corporation areas. For these five Legislative Assembly Constituencies, I announce to get the MLA Priority schemes of these urban areas funded through the National Housing Bank under Urban Infrastructure Development Fund (UIDF).

- ✓ In line with our Government's resolve for ‘Vayvastha Parivartan’, I also announce a change in the composition of MLA priority schemes from the financial year 2024-25. Now the Honourable MLAs will give priority for three really new schemes of roads, bridges, drinking water supply schemes or minor irrigation/sewerage schemes. Apart from this, one of the above priorities can be given related to the maintenance of any previously constructed schemes in these sectors. The fifth priority will be related to running electric buses on the existing routes of HRTC and necessary charging stations for running them.
- ✓ Provision has been made under the Vidhayak Kashetra Vikas Nidhi Yojana' to replace the overhanging electrical cables and for completion of incomplete ‘Mukhya Mantri Lok Bhawans’. Apart from this, as per the guidelines of ‘Mukhya Mantri Awas Yojana', the Hon’ble MLAs can make recommendations for construction of houses for any category of beneficiaries under the scheme.

- ✓ I also announce to revise the current limit for MLA priorities from Rs.175 crore to Rs.195 crore with an increase of Rs.20 crore. To take the state forward on the path of green development, out of the increased limit of Rs.20 crore, the priorities will be related to running the electric buses and charging stations.
- ✓ MLA Discretionary Grant (DG) will be increased from Rs.13 lakh to Rs.14 lakh per Legislative Assembly Constituency.
- ✓ The annual allocation of funds under 'Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana' will be increased from Rs.2 crore 10 Lakh to Rs.2 crore 20 Lakh per Legislative Assembly Constituency.

187. Speaker Sir, the public representatives are under tremendous pressure for starting capital works which have financial implications much more than the available resources. In the process new works start every year whereas already ongoing works compete with one another for resources. All the elected representatives would agree with me that the ongoing incomplete works need to be given priority. I announce that at least Rs.1,000 crore will be spent during 2024-25 for completion of ongoing works with the emphasis on those works which are near completion. This is for the first time in the history of the State that importance is being given for completion of ongoing works.

Employees Welfare.

188. Speaker Sir, our Government appreciates the important contribution of Government employees and pensioners in the development of the State. Our Government is sensitive to the need to pay arrears of

their increased salaries. Employees and pensioners are also aware of the precarious financial situation that the present Government inherited from the previous Government. For decades, Himachal Government has been following the pay scales of Punjab Government. Till now the Punjab Government has not paid the arrears of its employees and pensioners. Our Government strongly believes that with the cooperation of the employees, the financial condition of the State will soon improve.

189. Despite difficult fiscal situation, I make the following announcements:—

- Payment of arrears related to salary and pension of all employees and pensioners will be started in a phased manner starting from 1st March, 2024.
- Payment of arrears related to leave encashment and gratuity in respect of employees retired between 1st January, 2016 to 31st December, 2021, will be started in a phased manner starting from 1st March, 2024.
- I also announce that the Dearness Allowance (DA) instalment of 4 percent will be released from 1st April, 2024. Approximately Rs.580 crore will be spent annually on this.
- Till now the employees of the state can avail the All India Leave Travel Concession (LTC) only once at the end of their service period. I am happy to announce that after 1st April,

2024, the employees of the State will be able to avail the benefit of LTC at least twice during their service.

- Daily wagers will get Rs.400 per day with an increase of Rs.25.
- With above increase, the outsourced workers will get minimum wages of Rs.12,000 per month.
- Panchayat Veterinary Assistant will now get Rs.7,500 with an increase of 500 per month.

Our Government strongly believes that with the cooperation of the employees, the financial condition of the State will soon improve.

Budget Estimates.

190. Speaker Sir, now, I come to the Revised Estimates for 2023-24. According to the revised estimates for the year 2023-24, the total revenue receipts are Rs.40,446 crore. According to the revised estimates of 2023-24, the total revenue expenditure is estimated to be Rs.45,926 crore. According to the revised estimates for 2023-24, the revenue deficit of Rs.5,480 crore is estimated.

191. Speaker Sir, I am presenting a budget of Rs.58,444 crore for the year 2024-25.

192. Revenue receipts in the year 2024-25 are estimated at Rs.42,153 crore and total revenue expenditure is estimated at Rs.46,667 crore. Thus, the total revenue loss is estimated at Rs.4,514 crore. The fiscal deficit is estimated at Rs.10,784 crore which is 4.75 percent of the State's gross domestic product.

193. According to the budget of 2024-25, out of every Rs.100 expenditure, Rs.25 will be on salaries, Rs.17 on pension, Rs.11 on interest payment, Rs.9 on loan repayment, Rs.10 on grants for autonomous institutions, while the remaining Rs.28 Expenditure will be spent on other activities including capital works. Full details of next year's Budget are available in the detailed Budget documents being presented in this august House. Apart from this, FRBM Statement is also being presented along with the budget.

194. Speaker Sir, the main points of this budget address are shown in the Annexure.

Speaker Sir, with this I present this budget for the approval of the Honourable House.

Jai Hind – Jai Himachal

Annexure

Budget Highlights

Main Points of Budget:-

- **Budget size proposed as Rs.58,444 crore.**
- **During 2023-24:-**
  - **State Economy is expected to grow at 7.1 percent.**
  - **Per Capita Income is estimated as Rs.2,35,199.**
  - **State Gross Domestic Product estimated as Rs.2,07,430 crore.**
- **'Self-reliant Himachal'**
- Prosperous Farmer Himachal
- Green and Clean Himachal
- Electricity State Himachal
- Tourism State Himachal
- Skilled and Innovative Himachal
- Healthy and Educated Himachal
- Investor Friendly Himachal
- Drug Free Himachal
- Illegal Mining Free Himachal
- Prosperous Himachal

1. Prosperous Farmer Himachal

- ✓ Making farmers 'Self-reliant' by creating self employment and employment opportunities through natural farming.
- ✓ 36,000 farmers adopting the natural farming.
- ✓ 20 quintals of naturally grown grains per family will be procured by the Government at the MSP of Rs.40 per kg and maize at the rate of Rs.30 per kg.

- ✓ equitable development of 2,500 agricultural clusters over a period of 3 to 5 years under 'Himachal Pradesh Agriculture Mission' by promoting high value crops.
- ✓ A detailed action plan will be prepared to promote the production of coarse grains in the State.
- ✓ New mandis at Mehndali and Shilaru in Shimla district and Bandrol in Kullu district.
- ✓ Paonta Sahib, Khairi, Ghanduri and Nauhradhar in Sirmaur; Chauribihal, Patlikuhal and Khegsu in Kullu; Takoli and Kangni in Mandi; Jasur, Passu and Palampur in Kangra; and, Parwanoo, Kunihar and Waknaghat mandis in Solan will be upgraded.
- ✓ Chat Bot and AI based tools will be provided on the web enabled agriculture portal and mobile app will be launched enabling access to land records.
- ✓ A **'Centre of Excellence for Vegetable Nursery Production'** will be established.
- ✓ Minimum support price from the current Rs.38 per litre to Rs.45 per litre; and, from Rs.47 to Rs.55 per litre, respectively with effect from 1st April, 2024.
- ✓ **'Fully Automated Milk and Milk Products Plant'** at Dhagwar in Kangra.
- ✓ 'Milk Processing Plants' with modern technology will be established in Una and Hamirpur.
- ✓ 200 refrigerated milk vans will be provided to the local youth at a subsidy of 50 percent for transporting the milk.
- ✓ **'Artificial Insemination Training Centre'** at Darlaghat in Solan district.
- ✓ From 1st April, 2024, the fees charged by APMC from milk producing societies will be waived-off.

- ✓ A new scheme **"Bhed Bakri Paalak Protsahan Yojana"** for FMD Vaccine, deworming medicine and other medicines for sheep and goats.
- ✓ Task Force will give suggestions to construct new and maintain and operate the existing Cow-Sanctuaries and Gau-Sadans.
- ✓ An increase in financial assistance of Rs.700 to Rs.1,200 per cow per month for dependent cows in the private Gaushalas.
- ✓ A **'Centre of Excellence in Horticulture'** will be established at a cost of Rs.12 crore which will act as 'One Stop Resource Centre'.
- ✓ A '**Foundation Block'** for mother trees/bud wood banks will be set up for the promotion of guava, lemon and other sub-tropical fruits.
- ✓ Use of universal carton will be started from the apple season for 2024.
- ✓ Fishermen will be given financial assistance for construction of new fishing ponds in an area of 20 hectares at a subsidy of 80 percent.
- ✓ A new 'Centre of Excellence' having a 'Carp Fish Farm' will be established in Hamirpur District.
- ✓ 10 new large 'Biofloc Fish Production' ponds and 10 new small scale 'Biofloc Fish Production' units will be established.
- ✓ Three new 'Feed Mills' will be established.
- ✓ 150 new trout fish production units and two new trout hatcheries will be established.

2. Green, Clean and Energy State Himachal

- ✓ Largest 'Solar Power Project' with 32 MW capacity located at Pekhubella will be commissioned by the end of March, 2024.
- ✓ The 'Aghlor Solar Power Project' with an installed capacity of 10 MW in Una will be ready for commissioning by June, 2024.

- ✓ Bhanjal (Una) Solar Power Project with an installed capacity of 5 MW will be dedicated to the people of the State by September, 2024.
- ✓ The implementation of 'Rajiv Gandhi Start-up Yojana', envisaging the installation of solar panels ranging from 100 to 500 KW on the owned land at 45 percent subsidy will be given pace.
- ✓ Grid connected Solar Roof Top Plants and 'Solar Water Heating System' will be installed in the Baal-Baalika Aashrams and old age homes in the State.
- ✓ A detailed action plan will be implemented across the State under Re-vamped Distribution Sector Scheme (RDSS) to reduce Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses.
- ✓ The work on 4 transmission lines and 6 Extra High Voltage (EHV) sub-stations will be completed for Efficient Transmission and Distribution Network along with robust power generation.
- ✓ 327 additional diesel buses will be replaced with electric buses.
- ✓ Under the 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana', 10,000 permits will be given to run e-taxis at 40 percent subsidy.
- ✓ Eligible vehicles of the Forest Department, HRTC, HPTDC and GAD will be replaced with e-vehicles.
- ✓ Under the 'Vehicle Scraping Policy'**, "Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** will be established.
- ✓ The pursuit of a 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks will be set-up.
- ✓ For the Green and overall development and empowerment of the rural population of the State, I announce the launch of the **"Mukhya Mantri Harit Vikas Chhattravriti Yojana"**
- ✓ a Need Assessment Study (NAS) will be initiated in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the GIZ for mitigating the adverse effects of changing climate for sustainable development of agriculture and horticulture sectors.

- ✓ All the processes related to Forest Clearances were simplified to speed up the pace of development works by constituting district level committees.

3. <u>Tourism State Himachal</u>

- ✓ the Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan will be finalized soon and the land acquisition work will be started for expansion of Gaggal Airport.
- ✓ Out of the total 16 proposed heliports in the State, 9 heliports viz. Jaskot in Hamirpur; Rakkar and Palampur in Kangra; Sultanpur in Chamba; Aaloo Ground, Manali in Kullu; Sharbo in Kinnaur; and, Jispa, Sissu and Rangrik in Lahaul-Spiti will be developed in the first phase
- ✓ Chandratal, Kaza and Tandi in Lahaul-Spiti and Rackchham and Nako – Chango – Khab in Kinnaur will be developed as toursit destinations.
- ✓ Sky Walk Bridge will be constructed in the famous tourist place Haasan Valley near Kufri.
- ✓ All the Home Stay Units located in the State will be brought under the ambit of the 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act'.
- ✓ A master plan has been prepared for the development and management of Pong Dam under Swadesh Darshan-2.
- ✓ Construction work of a 3.2 Kilometres long ropeway at a cost of Rs.272 crore will be started between Bijli Mahadev and Mohal in Kullu.
- ✓ Broad gauge rail line from Kalka to Parwanoo for the convenience of the tourists and people of the State.

4. <u>Healthy, Educated, Skilled and Innovative Himachal</u>

- ✓ **"State Cancer Institute"** to be established in in 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' with the latest State of the Art diagnostic and treatment facilities.

- ✓ To provide the facility of chemotherapy and Palliative Care to the patients suffering from cancer in the State, **"Cancer Day Care Centres"** will be established in the district hospitals and selected 'Adarsh Swasthya Kendras'.
- ✓ A Linear Accelerator (LINAC) machine will be set up at a cost of Rs.21 crore at Indira Gandhi Medical College, Shimla.
- ✓ Rs. 1 crore per Centre will be made available for procuring machinery and equipment to be provided in 69 'Adarsh Swasthya Kendras'.
- ✓ Pace be given to all the works in progress in PGI Satellite Centre, Una Centre.
- ✓ 'Hospital Management Information Service (HMIS)' will be established in 53 health institutions of the State.
- ✓ **"State level Scrub Typhus Research Unit"** will be established.
- ✓ 'Lactation Management Centres' will be established in Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda and Kamla Nehru Hospital, Shimla.
- ✓ One 'Integrated Public Health Lab' with all test facilities will be established in each district.
- ✓ The General Nursing and Midwifery (GNM) school in Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda will be upgraded to Nursing College.
- ✓ A 'Guest Worker Screening Project' will be started for screening of migrant workers.
- ✓ Necessary reforms with the help of national level domain experts in 'HIMCARE' and 'SAHARA'.
- ✓ Quality class-rooms with appropriate size, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, learning software, proper seating facilities; full strength of teachers, playground, clean toilets along with other facilities will be provided.

- ✓ 'National Education Policy', 5+3+3+4 education system will be implemented at the school level in the State, which will also include a three year pre-school ‘Baal Vaatika’ curriculum.
- ✓ Educational institutions will be developed as ‘Institution of Excellence (IOE)’ in a phased manner.
- ✓ Start **“Apna Vidyalaya-Mera Vidyalaya-Mera Samman”** scheme for better coordination between schools and society and to increase community participation.
- ✓ In every Sub-Division, the Sub-Divisional Officers will have to compulsorily organize a review meeting of all the primary schools once in a month by rotation.
- ✓ Annual ranking of all the educational institutions of the State and the system of giving ‘Performance Based Grant' to them will be started.
- ✓ To develop the culture of reading and teaching, a massive public campaign in the name of **“Padho Himachal”** will be started.
- ✓ To make the training of teachers more result oriented, changes will be made in the rules of District Institute of Education Training (DIETs) and State Council of Educational Research (SCERT) and their functioning will be re-oriented to make them effective. Similarly, State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) will be reorganized and made functional.
- ✓ Children of Government schools will be provided with a safe and clean water bottle.
- ✓ Courses on the history and culture of Himachal, Indian Constitution, health, and other subjects of general knowledge will be started compulsorily from class five.
- ✓ Construction of a library and a reading room with modern facilities each at every district and sub-divisional headquarters and Gram Panchayats.

- ✓ Start the construction work of five Rajiv Gandhi Day Boarding Schools, namely Lahdoo and Nagrota Bagwan (Kangra), Amlehar and Bhoranj (Hamirpur), and Sanghnai (Una).
- ✓ More private sector employers will be added to EEMIS portal of the Labour and Employment Department.

5. <u>Investor Friendly Himachal</u>

- ✓ Targeted to complete 4 antifreeze drinking water projects in Kinnaur, Chamba and Lahaul & Spiti.
- ✓ The work of drinking water supply schemes with the capacity of 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) will be completed in Jawali, Hamirpur, Baijnath-Paprola and Ner Chowk.
- ✓ Work on drinking water improvement schemes for Nahan, Arki, Nirmand, Palampur and Joginder Nagar will be started soon.
- ✓ Upgradation of 500 Kilometres of roads and Construction of 325 Kilometres of new roads and 8 bridges.
- ✓ 15 habitations will be connected by road.
- ✓ 205 Kilometres long new roads, cross drainage work on 305 Kilometres long roads, 425 Kilometres long tarred roads and 27 bridges will be constructed under RIDF through NABARD.
- ✓ Repair work of damage caused by rain on Jiya-Manikaran road, Upgradation of Shahpur - Sihunta - Chuwari road, Construction of a bridge connecting Terrace and Sthana on river Beas, Upgradation of Baghchhal-Mehre-Barsar road, Construction of bridge on Swan River at Pandoga Tiuri under the Central Road Infrastructure Fund (CRIF) will be completed.
- ✓ Calcium Chloride and Brine Solution will be used on high altitude roads so that ice layer does not accumulate on the surface of these roads in winter and possible accidents are avoided.
- ✓ **"Industrial Promotion and Investment Policy, 2024"** will be brought out.
- ✓ **"Start-up Policy, 2024"** will be brought out in 2024-25.

- ✓ The enhanced Electricity Duty will not be payable by those consumers who were granted relaxation in paying the ED till expiry of the admissible period as per the provisions of the 'Himachal Pradesh Industrial Policy, 2019'.
- ✓ **"Himachal Pradesh Mines and Minerals Policy, 2024"** will be introduced.
- ✓ Road from Sheetalpur to Jagatkhana in this area at a cost of Rs.70 crore will be constructed.
- ✓ 'Himachal Pradesh Film Policy, 2024' will be implemented from 2024-25.
- ✓ 'Film Facilitation Cell' will be established in the Information and Public Relations Department.
- ✓ A dedicated web portal will be set up to submit online applications and grant permissions for shooting of films.
- ✓ The MLA Priority schemes of 5 urban areas to be funded through the National Housing Bank under Urban Infrastructure Development Fund (UIDF).

6. <u>Drug Free Himachal</u>

- ✓ **"Model Drug Prevention and Rehabilitation Centre"** will be established in Kandaghat.
- ✓ An 'effective monitoring and reporting system' starting from sub-division level right up to State level with clear cut responsibilities.
- ✓ Construction of an indoor stadium with modern facilities in Hamirpur.
- ✓ Construction of an indoor stadium in Panjoa, Una.
- ✓ Construction of an Indoor Sports Stadium for Manali in Bandrol.
- ✓ Construction of Indoor Stadium with swimming pool facility in Rehan.
- ✓ Construction of Indoor Stadium with swimming pool in Dehra.

- ✓ Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Kharidi, Nadaun.
- ✓ Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Kasumpati.
- ✓ Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Jaisinghpur.
- ✓ Construction of Indoor Multipurpose Sports Complex at Dhalli Bypass.
- ✓ The prize money for winning a gold medal in an individual event in the Olympic Games is Rs.5 crore, for a silver medal it is Rs.3 crore and for a bronze medal it is Rs.2 crore.
- ✓ The prize money for winning gold medal in individual event in Asian Games will be Rs.4 crore, for silver medal it will be Rs.2.5 crore and for bronze medal it will be Rs.1.5 crore.
- ✓ The prize money for winning gold medal in individual event in the Commonwealth Games will be Rs.3 crore, for silver medal it will be Rs.2 crore and for bronze medal it will be Rs.1 crore.
- ✓ Based on the medals received by the winning Himachali players in team events, the above prize money will be given to each player in equal proportion to the representation.
- ✓ 3 Tier fare for players who participate in sports events outside the State up to a distance of 200 kms and economy class air fare for traveling to places beyond 200 kms.
- ✓ The number of existing 43 sports included under 3 percent sports quota will be increased to give excellent players various posts in government departments.
- ✓ Diet money of Rs.250 per day will be given to primary education level players for participating in sports held in the State.
- ✓ Diet money of Rs.400 per day to all other players for participating in the games being held in the State.

- ✓ Diet money of Rs.500 per day is given to all the players for participating in games held outside the State.
- ✓ All the players staying in the sports hostels of the State will be given diet money of Rs.250 and Rs.400 as above.

7. <u>Illegal Mining Free Himachal</u>

- ✓ Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Cameras will be provided at all transport barriers so that tax evasion can be eliminated and the government can get additional resources.
- ✓ Introduction of 'mobile app' for payment of VAT and other taxes for the convenience of taxpayers.
- ✓ 'Kardaata Samvaad Abhiyaan' will be started with the aim of taking feedback from various taxpayers at important industrial and business centers located in the state and getting information about the problems faced by them.
- ✓ GIS Based App to be launched aimed at curbing illegal and illegal activities.

8. <u>Prosperous and Inclusive Himachal</u>

- ✓ 40,000 new eligible beneficiaries of old age, widow, single woman, disabled, leprosy patients and transgender pension are included in this scheme.
- ✓ Establishment of a **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** in Kandaghat for higher education of disabled people. In this, financial assistance will be provided for rent for accommodation for eligible disabled children including residential facilities, play ground and all other facilities.
- ✓ Residential facilities, play grounds and all other facilities for disabled children in the age group of 0-27 years.
- ✓ **"Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)"**to be shifted to **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"**.

- ✓ New scheme **"Mukhya Mantri Sukh Arogya Yojana"** started. Under this, free medical facility is provided to all the elderly people above 70 years of age in the state who are not paying income tax.
- ✓ A new scheme **"Mukhya Mantri Sukh-Shiksha Yojana"** started. Under this, the state government will bear the expenses on the education of children up to 27 years of age of all such widows in the state.
- ✓ Rs 1,000 per month will be given in the account of all eligible children of widows, destitutes, divorced and disabled parents till they attain the age of 18 years.
- ✓ According to the market demand for Scheduled Castes, Tribes and Other Backward Classes, etc., GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD will be introduced.
- ✓ New scheme "Maharishi Valmiki Kamgar Awas Yojana" started for the brothers and workers of Valmiki community to help them in construction of houses.
- ✓ Increase in MGNREGA daily wage by Rs.60. Widow, Single/ Destitute/Divyang Women MGNREGA Workers will be given assistance up to Rs.3 lakh to build houses.
- ✓ Under "Mukhya Mantri Vidhwa Evam Ekal Nari Awas Yojana', the amount of assistance increased to Rs.3 lakh.
- ✓ 363 houses will be allotted to Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers in Municipal Corporation Dharamshala, Solan and Shimla and Municipal Council Nalagarh and Parwanoo, whose annual income is less than Rs.3 lakh.
- ✓ Artificial Intelligence (AI) along with data analytics will be started for evidence based policy formulation.
- ✓ Amendments in the Right of Way (RoW) Portal for expeditious disposal of online applications for 5G connectivity made by investors.

- ✓ The work of upgradation of State Data Centre (SDC) will be completed by August, 2024.
- ✓ After successful implementation of Him Parivar Registry, various citizen services will be integrated with it.
- ✓ For online challan, e-Challan and e-POS Machines will be made available to the departmental officers.

9. Welfare of Employees, Para-workers, MGNREGA Workers and others

- ✓ Payment of arrears related to salary and pension of employees and pensioners will start in a phased manner from 1st March, 2024.
- ✓ Payment of arrears related to leave encashment and gratuity in respect of employees retired between 1st January, 2016 to 31st December, 2021, will start in a phased manner from 1st March, 2024.
- ✓ Installment of dearness allowance at the rate of 4 percent from 1st April, 2024.
- ✓ After April 1, 2024, employees of the state will get the facility of LTC at least twice during their service period.
- ✓ Daily wage earners will get Rs.400 per day with an increase of Rs.25.
- ✓ Outsourced workers will now get a minimum of Rs.12,000 per month.
- ✓ The salary of Panchayat Veterinary Assistant will be increased to Rs.7,500.
- ✓ With increased honorarium, now Rs.10,000 monthly to Anganwadi workers, Rs.7,000 to Mini Anganwadi workers, Rs.5,500 to Anganwadi Sahayika, Rs.5,500 to Asha worker, Rs.4,500 to Mid Day Meal Workers, Rs.5,000 to Water Carrier (Education Department). , Rs.5,300 to Jal Rakshak, Rs.5,000 to Multi Purpose Workers of Jal Shakti Vibhag, Rs.6,300 to Para Fitter and Pump-Operator, Rs.400 per day wage to daily wage

earners with an increase of Rs.25, minimum wage to outsourced workers now Rs.12,000, Panchayat Chowkidar will get Rs.8,000, a Revenue Chowkidar will get Rs.5,800, a Revenue Lambardar will get Rs.4,200 per month. With this, there will be an increase of Rs.500 per month in the honorarium of sewing teachers, Rs.1,900 per month in the honorarium of IT teachers, Rs.1,900 per month for SMC teachers and Rs.500 per month for SPOs.

- ✓ In Panchayati Raj institutions, the increase in honorarium of Chairman Zila Parishad is Rs.4,000, Vice Chairman is Rs.3,000, Member Zila Parishad is Rs.1,300, Chairman, Panchayat Samiti is Rs.1,900, Vice Chairman Panchayat Samiti is Rs.1,400, Member, Panchayat Samiti is Rs.1,200 per month, Pradhan, Gram Panchayat is Rs.1,200, UP-Pradhan Gram Panchayat is Rs.800 per month and increase of Rs.250 is in the honorarium received per meeting by the member Gram Panchayat.
- ✓ In local municipal bodies, the increase in the honorarium of the Mayor is Rs.4,000, of the Deputy Mayor Municipal Corporation is Rs.3,000, of the Councilor Municipal Corporation is Rs.1,400, of the Chairman Municipal Council is Rs.1,700, of the Vice Chairman Municipal Council is Rs.1,400, of the Councilor Municipal Council is Rs.700, of the Pradhan Nagar Panchayat is Rs.1,400, of the Up-Pradhan Nagar Panchayat , Rs.1,100, and of Member Nagar Panchayat is Rs.700.
- ✓ Appointment of one Van Mitra in all 2,061 forest beats.
- ✓ Recruitment for 100 vacant posts of Forests Guards in Forest Department.
- ✓ Diet money of police personnel increased to Rs.1,000.

10. <u>Others</u>

- ✓ Fitness mandatory for all vehicles through Automated Testing Centres.
- ✓ After completing the construction work of Baglamukhi Ropeway, it will be dedicated to the people of the State.

- ✓ Plan to cut about 13 thousand Khair trees in 10 Forest Divisions. This will also increase the revenue of the state.
- ✓ Will also file a petition in the Hon'ble Supreme Court for permission to cut Chil trees. This will not only generate additional revenue but will also improve the quality of the Eco-System Services.
- ✓ The work of getting the land records translated into various languages listed in Schedule III of the Constitution will start soon.
- ✓ Residential facilities for police staff working in the premises or in the vicinity of police stations located in urban areas.
- ✓ Opening of new sub fire station at Changar Baroh in Kangra, fire post at Kotli and Ladbhadol in Mandi and upgradation of sub fire station at Theog to fire station.
- ✓ Fire fighting units will open in Nirmand, Kunihar and Ubadesh (Kotkhai), Chhota Bhangal and Chuhar Valley of Kangra.
- ✓ The current limit of financial limit for MLA priorities schemes will be increased from Rs.175 crore to Rs.195 crore.
- ✓ 'MLA Discretionary Grant' will be increased from Rs.13 lakh to Rs.14 lakh per assembly constituency.
- ✓ Under 'Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana', the amount per assembly constituency is Rs.2 crore 20 lakh.
- ✓ In 2024-25, Rs.1,000 crore will be spent on works which are near completion.

****